आज का विचार
जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा। जिसे जीना नहीं आता वह सुविधाओं के होते हुए भी दुखी ही मिलेगा।

दैनिक सिटी दर्पण

आईना सच का

सिटी दर्पण-राष्ट्रीय दैनिक हिंदी समाचार पत्र की अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें।

चंडीगढ़ । बुधवार, 3 जून, 2026 | वर्ष 24, अंक 134, मूल्यः 3 रुपए, पृष्ठ 8 | RNI Regn No.: CHAHIN/2003/09265 Established 2003 | www.citydarpan.com

भगवंत मान द्वारा किसानों के लिए ऐतिहासिक ऐलान, किसान क्रेडिट कार्ड की कर्ज सीमा में वृद्धि

किसानों को अब के.सी.सी. योजना के तहत फसल की लागत के बराबर कर्ज मिलेगा और ब्याज दरें भी काफी कम होंगी: भगवंत सिंह मान

यज्ञांश शर्मा
चंडीगढ़

पिछले कुछ दशकों के दौरान पंजाब में हुए कृषि सुधारों में सबसे बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) प्रणाली में ऐतिहासिक सुधार किया है। इसके तहत 26 साल पुराने उस ढांचे को बदल दिया गया है जिसने किसानों को लंबे समय से अपर्याप्त संस्थागत कर्ज पर निर्भर रहने और साहूकारों के रहमो-करम पर छोड़ दिया था।

यह नई नीति फसल की वास्तविक लागत के अनुसार फसल-वार कर्ज की सीमा (क्रेडिट लिमिट) को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है, ब्याज के बोझ को कम करती है, अधिक मुनाफे वाली फसलों और सहायक क्षेत्रों के लिए कर्ज की पात्रता का विस्तार करती है। यहां तक कि पराली प्रबंधन के लिए विशेष वित्तीय सहायता शुरू करती है और किसानों को ए.टी.एम. और यू.पी.आई. जैसे आधुनिक डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से धन का उपयोग करने में सक्षम बनाती है।

इन सुधारों को कृषि को अधिक लाभदायक और टिकाऊ बनाने की दिशा में अहम फैसला बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि नया के.सी.सी. ढांचा किसानों के हाथों में अधिक पैसा सीधे पहुंचाएगा, गेहूं-धान के चक्र से बाहर फसल विविधता को तेज करेगा, सहकारी कर्ज संस्थाओं को मजबूत करेगा और किसानों को कर्ज के जाल से बाहर निकालने में मदद करेगा। इन सुधारों से पंजाब भर के 13 लाख से अधिक किसानों को लाभ होने की उम्मीद है, जिसमें कई फसलों के लिए कर्ज सहायता में भारी वृद्धि होगी। इसमें बागवानी फसलें भी शामिल हैं, जहां पहले मिलने वाली 32,000 रुपए प्रति एकड़ की एकसमान सीमा के मुकाबले अब कर्ज 1.57 लाख रुपए प्रति एकड़ तक जा सकता है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, यह सिर्फ कोई नीतिगत बदलाव नहीं है, बल्कि पंजाब के किसानों की आर्थिक आजादी के उद्देश्य से लिया गया ऐतिहासिक फैसला है। हमने लाल फीताशाही को समाप्त कर दिया है, यह सुनिश्चित किया है कि अधिक पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचे और प्राथमिक कृषि सहकारी सभाओं (पी.ए.सी.एस.) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए प्रभावी ढंग से किसानों की सेवा करना आसान बना दिया है। हमने अपने किसानों को 21वीं सदी के डिजिटल साधनों से लैस किया है और वे अब पंजाब की तरक्की की नई कहानी लिखेंगे।

इस सुधार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबा सरकार ने वर्ष 2000 से चले आ रहे पुराने के.सी.सी. सिस्टम को बदलकर 26 सालों की स्थिरता को तोड़ा है। उन्होंने कहा, दो दशकों से अधिक समय से पंजाब के किसानों को हाथों-हाथ कागजी कार्रवाई, चेक बुक और पासबुकों के आस-पास घूमने वाले पुराने और जटिल के.सी.सी. ढांचे पर निर्भर रहने के लिए मजबूर किया गया था। पिछली सरकारों ने इस स्थिति को सुधारने के बजाय ज्यों-का-त्यों रहने दिया। हमारी सरकार ने उस 26 साल पुराने सिस्टम को बदलकर पारदर्शी, डिजिटल और बेहतरीन कर्ज व्यवस्था लागू की है, जो कि आधुनिक कृषि की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि संशोधित नीति से किसानों को मिलने वाली कर्ज सीमा में भारी वृद्धि होगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बैंक कर्ज फसल की वास्तविक लागत को दशार्ता हो। उन्होंने कहा, हमने गेहूं के लिए कर्ज सीमा 24,380 रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रति एकड़ कर दी है। इसी तरह धान के लिए 25,440 रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर 39,000 रुपए प्रति एकड़ कर दिया गया है। इससे किसानों को वह वास्तविक वित्तीय सहायता मिलेगी जिसके वे हकदार हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि के.सी.सी. के नए ढांचे में फसलों के अवशेष प्रबंधन को शामिल करने वाला पहला सूबा बनकर पंजाब, देश भर में अग्रणी सूबे के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा, धान की संशोधित 39,000 रुपए प्रति एकड़ की सीमा में से 2,000 रुपए प्रति एकड़ विशेष रूप से फसली अवशेष प्रबंधन के लिए रखे गए हैं। देश में पहली बार किसानों को पराली प्रबंधन के लिए विशेष सहायता के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने के लिए वित्तीय रूप से मजबूत किया जा रहा है। मान ने कहा कि सरकार द्वारा गन्ना उत्पादकों की सहायता के लिए भी शानदार कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा, लगाए गए गन्ने के लिए कर्ज सीमा को 44,000 रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर 1 लाख रुपए प्रति एकड़ कर दिया गया है।

इस वर्ष हरियाणा में अनाज भंडारण के लिए 20 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम बनाए जाएंगे: नायब सैनी

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विजन-2047 के तहत खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अगले 5 साल के रोडमैप व कार्ययोजना की समीक्षा बैठक में दिए विस्तृत दिशा-निर्देश

भूपेंद्र शर्मा
चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसान द्वारा मेहनत से उगाए गए अनाज को खराब होने से बचाने के लिए हरियाणा में अनाज भंडारण की समुचित व्यवस्था की जाएगी। इसके अंतर्गत इस साल हरियाणा में 20 लाख मीट्रिक टन क्षमता के नए गोदाम बनाए जाएंगे जिसके लिए अधिकारी पूरी तैयारी करके लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में जुट जाएं। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश मंगलवार को हरियाणा सिविल सचिवालय में हरियाणा विजन-2047 के तहत खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अगले 5 साल के रोडमैप व कार्ययोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री जे गणेशन ने बताया कि अनाज का खुले में भंडारण अथवा उचित भंडारण के अभाव के कारण प्रदेश में अनाज का 4 से 5 प्रतिशत तक नुकसान हो जाता है। इस नुकसान से बचने के लिए कवर्ड स्टोरेज की व्यवस्था करनी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इस समय प्रदेश में गेहूं का 115 लाख मीट्रिक टन, चावल का 71 लाख एमटी, फल व सब्जियों का 110 लाख एमटी तथा दूध व अन्य डेयरी उत्पादों का 115 लाख एमटी उत्पादन होता है। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा में हरियाणा का योगदान लगभग 25 प्रतिशत है। इस समय हरियाणा में 66 लाख मीट्रिक टन अनाज भंडारण की क्षमता है जिसे 130 लाख एमटी तक बढ़ाने की आवश्यकता है।

इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्यान्न के नुकसान पर रोक लगाने के लिए कवर्ड स्टोरेज के निर्माण, कोल्ड स्टोरेज की क्षमता बढ़ाने और उपलब्ध संसाधनों का उचित इस्तेमाल करने की कार्ययोजना बनाई जाए। सभी संबंधित विभागों के आपसी समन्वय के साथ इस वर्ष पीपीपी मोड में 20 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम बनाने का लक्ष्य पूरा किया जाए ताकि अनाज को खराब होने से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनाज, बागवानी फसलों, सब्जियों तथा फलों के उचित भंडारण के लिए अगले 5 साल के भीतर एक ऐसी कार्ययोजना को मूर्त रूप दिया जाएगा जिससे उत्पादित खाद्यान्न का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बने गोदामों को ऊर्जा उत्पादन का भी माध्यम बनाया जाए। सभी गोदामों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर इन्हें ग्रिड से जोड़ा जाए ताकि बिजली का उत्पादन बढ़ाया जा सके। इसी प्रकार मंडियों व गोदामों में मजदूर की पीठ पर बोरी लादने की बजाय इस कार्य के लिए कन्वेयर बैल्ट अथवा अन्य तकनीकी व्यवस्था के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री जे गणेशन ने फसल के नुकसान पर रोक लगाने तथा मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभाग द्वारा अगले 5 वर्षों के दौरान किए जाने वाले कार्यों का खाका प्रस्तुत करते हुए बताया कि इससे 3000 से 5000 करोड़ रुपये के नुकसान को रोका जा सकेगा। इस अवसर पर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री जे गणेशन, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की प्रधान सचिव श्रीमती अमनीत पी कुमार, मुख्यमंत्री के ओएसडी व स्वर्ण जयंती हरियाणा राजकोषीय प्रबंधन संस्थान के महानिदेशक डॉ. राज नेहरू तथा मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री यशपाल यादव सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

प्रतिभा को केवल अवसर और मार्गदर्शन की जरूरत: राष्ट्रपति

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने ह्यजनजातीय गरिमा उत्सवह्न के अंतर्गत आयोजित ह्यनव भारत में बिरसा की जीवंत विरासत सप्ताहह्न के दौरान छात्रवृत्ति योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता केवल उसे खोजने, तराशने तथा उचित मार्गदर्शन और अवसर उपलब्ध कराने की है। यदि सही अवसर मिलें तो गांवों, दूरदराज के क्षेत्रों और जनजातीय अंचलों के युवा भी देश का नाम रोशन कर सकते हैं। राष्ट्रपति ने जनजातीय युवाओं का आान किया कि वे भगवान बिरसा मुंडा की विरासत से प्रेरणा लेकर विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

राष्ट्रपति ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित विशेष संवाद कार्यक्रम में मंत्रालय की प्रमुख छात्रवृत्ति योजनाओं के जनजातीय लाभार्थियों को संबोधित किया। यह कार्यक्रम 10 मई से 9 जून तक मनाए जा रहे ह्यजनजातीय गरिमा उत्सवह्न के तहत ह्यनए भारत में बिरसा की जीवंत विरासत सप्ताहह्न के दौरान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम, जनजातीय कार्य राज्यमंत्री दुगार्दास उइके, राष्ट्रपति की सचिव दीप्ति उमाशंकर, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी तथा मंत्रालय की तीन प्रमुख छात्रवृत्ति योजनाएं अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति, जनजातीय विद्यार्थियों के लिए उच्चस्तरीय शिक्षा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति और राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना के 200 चयनित लाभार्थी शामिल हुए।

राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने यह बताया कि भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं ने किस प्रकार उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है और उन्हें अपने सपनों को साकार करने का अवसर प्रदान किया है। ऐसी सफलता की कहानियां देशभर के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। देश के दूरस्थ गांवों और जनजातीय अंचलों में प्रतिभाशाली युवाओं की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता केवल यह सुनिश्चित करने की है कि उन्हें उचित मार्गदर्शन, सहयोग और मंच मिले। आज यहां उपस्थित विद्यार्थियों की उपलब्धियां इस बात का प्रमाण हैं कि अवसर मिलने पर जनजातीय समुदाय के युवा भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा सशक्तीकरण का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है तथा उसके जीवन की दिशा बदल सकती है। उनकी अपनी जीवन यात्रा में भी शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इसी कारण वे जनजातीय समाज के लोगों को शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करने का लगातार प्रयास करती हैं।

उन्होंने कहा कि व्यक्ति की वास्तविक पहचान उसके समाज, संस्कृति और परंपराओं से होती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पहचान को भूल जाता है तो वह अपने दायित्वों से भी दूर हो जाता है। इसलिए जनजातीय युवाओं को आधुनिक शिक्षा और तकनीक को अपनाने के साथ-साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को भी सहेजकर रखना चाहिए। आज भी अनेक प्रतिभाशाली छात्र केवल इसलिए अवसरों से वंचित रह जाते हैं क्योंकि उन्हें विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं और सरकारी सुविधाओं की जानकारी नहीं मिल पाती।

अल नीनो की आशंका पर केंद्र अलर्ट, किसान हित सर्वोच्च: शिवराज

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

दक्षिण-पश्चिम मानसून, संभावित अल नीनो प्रभाव, जल उपलब्धता, बीज व्यवस्था, फसल रणनीति और राज्यों की तैयारियों की मंगलवार को कृषि भवन में विस्तृत समीक्षा की गई। इस उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी संबंधित केंद्रीय विभागों, राज्य सरकारों को समन्वय और अग्रिम योजना के साथ काम करने के निर्देश दिए।

चौहान ने बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार पूरी सतर्कता के साथ तैयारी कर रही है और लक्ष्य यह है कि मौसम की चुनौती का असर खेत और किसान पर न्यूनतम रहे। उन्होंने कहा कि किसानों के हित सर्वोपरि हैं और संभावित अल नीनो प्रभाव को देखते हुए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी की जाएं। बैठक में मौसम पूवार्नुमान, जल उपलब्धता, फसलों की स्थिति, बीज एवं अन्य कृषि आदानों की व्यवस्था, राज्यों की तैयारियों और संभावित प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई।

चौहान ने स्पष्ट किया कि मौसम संबंधी पूवार्नुमानों को पूरी गंभीरता से लिया जा रहा है, लेकिन किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयास, बेहतर जल प्रबंधन, उन्नत तकनीक, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और जलवायु-सहनशील कृषि उपायों के कारण संभावित चुनौतियों का प्रभाव काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। उपलब्ध आकलन के अनुसार जलाशयों का भंडारण इस अवधि के सामान्य स्तर के 127.01 प्रतिशत पर है, जिससे खरीफ मौसम में सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी और नमी की कमी के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।

भाजपा छोड़ने की अटकलों के बीच अन्नामलाई ने की अमित शाह से मुलाकात

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) छोड़ने और नई पार्टी के गठन की अटकलों के बीच मंगलवार को तमिलनाडु भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मंगलवार को यहां मुलाकात की। इससे पहले अन्नामलाई ने पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन महासचिव बीएल संतोष से भी मुलाकात की। इस दौरान भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने अन्नामलाई से उनकी आगे की राजनीतिक योजनाओं पर पुनर्विचार करने को भी कहा है।

सूत्रों के मुताबिक के अन्नामलाई ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर तमिलनाडु की मौजूदा राजनीतिक उठापटक और नाराजगी की कारणों के बारे में बताया। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अन्नामलाई को थोड़ा इंतजार करने को कहा है। अमित शाह से मुलाकात कर लौटे के अन्नामलाई ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि मुझे जो बताना था वो मैंने बता दिया। आप इंतजार करें अगले दो दिनों में मिलकर बात करेंगे। अन्नामलाई बुधवार को भी दिल्ली में रहेंगे। उल्लेखनीय है कि पूर्व आईपीएस अधिकारी अन्नामलाई तमिलनाडु में भाजपा का बड़ा चेहरा माने जाते रहे हैं। हाल ही में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर नैनार नागेन्द्रन को यह जिम्मेदारी दी गयी। उसके बाद भाजपा के एआईएडीएमके के साथ गठबंधन के फैसले से भी वे खुश नहीं थे। अन्नामलाई ने सीबीएसई के 9वीं कक्षा के लिए त्रि-भाषा नीति लागू करने खिलाफ खुल कर टिप्पणी की थी। फिलहाल वे पार्टी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।

हमने शोहदों को ठीक किया, जो बोली से नहीं माना वो गोली से जरूर मान गया : योगी

एजेंसी (हि.स.)
कुशीनगर

कुशीनगर की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विकास बनाम अराजकता के मुद्दे पर कहा कि पहले की सरकारों के समय उत्तर प्रदेश कट्टा-बम बनाने वालों की पहचान से जुड़ा था, जबकि आज वही उत्तर प्रदेश देश की सुरक्षा के लिए ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा है। पिछली सरकारें निर्दोष लोगों, व्यापारियों को लूटने के लिए कट्टा-बम बनाती थीं। बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाती थीं, लेकिन हमने इन शोहदों को ठीक किया है। जो ठीक नहीं हुआ, बोली से नहीं माना वो गोली से जरूर मान गया है।

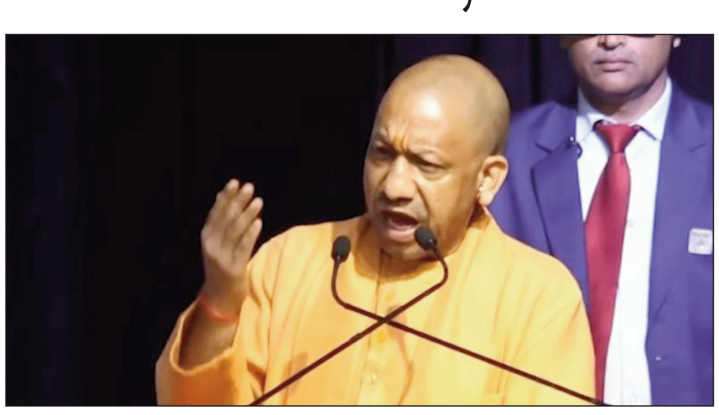

मंगलवार को कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक की 278 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों की विकृत मानसिकता ने कुशीनगर को बीमारी, भुखमरी और बेरोजगारी दी, लेकिन डबल इंजन सरकार ने इंसेफेलाइटिस और माफिया, दोनों पर प्रभावी प्रहार करते हुए विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण तैयार किया है। कुशीनगर अब पिछड़ेपन की पहचान नहीं, बल्कि बुलेट स्पीड से आगे बढ़ते नए उत्तर प्रदेश का प्रतीक बन रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम के पुत्र कुश, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की तपोभूमि कुशीनगर आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जबकि 9-10 वर्ष पहले यह जनपद पहचान के संकट, इंसेफेलाइटिस, माफिया राज, भूख, बेरोजगारी और अव्यवस्था से जूझ रहा था। खनन माफिया का आतंक था, किसान शोषण का शिकार था, उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता था, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं बदहाल थीं तथा फाजिलनगर व कसया क्षेत्र में मुसहर समुदाय के लोगों की भूख से मौत की खबरें आती थीं। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने नया रास्ता चुना और डबल इंजन सरकार के प्रयासों से कुशीनगर की तस्वीर बदल गई। आज जिले में लगभग 90 हजार गरीबों को आवास, 3.14 लाख से अधिक परिवारों को शौचालय, मुफ्त राशन, आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा सहित अनेक जनकल्याणकारी सुविधाएं मिल रही हैं। पहले दंगे, अपराध और अराजकता प्रदेश की पहचान बन गए थे, जबकि आज सुरक्षा, विकास और गरीब कल्याण नई पहचान है। बिना रुके, बिना डिगे और बिना झुके सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस कुशीनगर में कभी मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय और एयरपोर्ट की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी, आज वहां अपना मेडिकल कॉलेज, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जैसी सुविधाएं साकार रूप ले चुकी हैं। इसी सत्र से कृषि विश्वविद्यालय का संचालन शुरू होगा और बच्चों का प्रवेश कराया जाएगा। किसानों को गन्ने का मूल्य 315 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये प्रति कुंतल दिया जा रहा है तथा भुगतान भी समय पर सुनिश्चित किया जा रहा है। इंसेफेलाइटिस की बीमारी लगभग समाप्त हो चुकी है, ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश से माफिया राज समाप्त हुआ है। मच्छर बीमारी लाता था और माफिया बेरोजगारी, लेकिन डबल इंजन सरकार ने दोनों समस्याओं का समाधान किया है। आज कुशीनगर की बेटियां व युवा पुलिस समेत विभिन्न सरकारी नौकरियों में चयनित हो रहे हैं तथा निवेश से पैदा हो रहे नए रोजगारों का लाभ भी उठा रहे हैं।

एक वोट की ताकत से बना अयोध्या में भव्य राममंदिर

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में जनता के एक वोट की ताकत का परिणाम अयोध्या, लखनऊ और दिल्ली तक दिखाई देता है। इसी जनादेश की ताकत से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, जम्मू-कश्मीर से धारा 370 समाप्त हुई और उत्तर प्रदेश ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण केंद्र बन रहा है। जब भारत का बहादुर जवान दुश्मन की छाती पर ब्रह्मोस दागता है, तो पाकिस्तान बचाओ-बचाओ चिल्लाने लगता है। कुशीनगर के लोगों को अब विकास की राह पर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डबल इंजन सरकार विकास के लिए धन की कमी नहीं आने देगी और एक-एक पैसे का हिसाब रखते हुए हर क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। कुशीनगर कभी पिछड़ा नहीं था, बल्कि पिछली सरकारों की विकृत नीतियों ने इसे बीमारी, भुखमरी और बेरोजगारी के संकट में धकेल दिया था। अब यह जनपद विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा आधुनिक बुनियादी ढांचे के बल पर बुलेट स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर कुशीनगर के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, सांसद देवरिया शशांक मणि, गोरखपुर के सांसद रविकिशन, विधायक तमकुही राज डॉ. असीम कुमार, विधायक फाजिलनगर सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा, जिला पंचायत अध्यक्ष सावित्री जायसवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय एवं अन्य गणमान्य महानुभाव उपस्थित रहे।

लाभार्थियों को वितरित किए स्वीकृति पत्र, चेक एवं टूल किट

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न विभागों की योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, चेक एवं टूल किट वितरित किए। ग्राम विकास विभाग की मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत संध्या देवी एवं प्रियंका को आवास स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की कॉक्लियर इम्प्लांट योजना के तहत कुमारी श्रेया शर्मा एवं कुमारी कृति को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से जनगणना-2027 में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का किया आह्वान

कहा ,जनगणना डेटा के आधार पर ही स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की योजनाएं तैयार होंगी

सटीक आंकड़े ही लाएंगे सही विकासः मुख्यमंत्री

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को जनगणना-2027 के तहत चल रहे स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) अभियान में भाग लिया और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जनगणना संबंधी अपनी जानकारी दर्ज की।

इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश की जनगणना संचालन निदेशक दीप शिखा शर्मा और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को डिजिटल जनगणना की प्रक्रिया, इसकी प्रमुख विशेषताओं तथा नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने और 15 जून, 2026 तक अपनी स्व-गणना पूरी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और विकास की आधारशिला है, जो जनसंख्या, परिवारों की स्थिति, आवास, संसाधनों तथा सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच से संबंधित महत्त्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाती है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर विकास योजनाएं बनाई जाती हैं तथा जनकल्याणकारी नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जनगणना-2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण 16 जून से 15 जुलाई, 2026 तक संचालित किया जाएगा, जोकि गृह सूचीकरण एवं आवास जनगणना पर आधारित होगा। द्वितीय चरण में जनसंख्या गणना की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जाएगी। गणनाकर्ता (एन्यूमरेटर) और पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) मोबाइल उपकरणों के माध्यम से घरों और परिवारों से संबंधित जानकारी एकत्रित करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के दुर्गम बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों में जनसंख्या गणना 11 से 30 सितंबर, 2026 तक होगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में यह कार्य 9 से 28 फरवरी, 2027 तक संपन्न किया जाएगा। उन्होंने प्रदेशवासियों से इस राष्ट्रीय महत्त्व के अभियान को सफल बनाने के लिए गणनाकताओं, पर्यवेक्षकों तथा अन्य जनगणना अधिकारियों को सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाकर सहयोग करने का आग्रह किया।एक आधिकारिक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि सही और सटीक आंकड़ों से ही समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जनगणना के कार्यों को पूरी पारदर्शिता और सटीकता के साथ पूरा करें। साथ ही, उन्होंने आम जनता से अपील की कि जब प्रगणक (नियुक्त कर्मचारी) उनके घर पहुँचें, तो उन्हें पूरी और सही जानकारी उपलब्ध कराएं ताकि कोई भी नागरिक इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया से न छूटे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास और सही रणनीतियों को आकार देने के लिए सटीक आंकड़ों का होना बेहद जरूरी है। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि वे जनगणना के लिए आने वाले कर्मचारियों को सही डेटा देकर इस राष्ट्रीय कार्य को सफल बनाने में अपना नागरिक योगदान दें।

सील्ड रोड पर वाहनों को रोकने से भड़के वकीलों ने घेरा सचिवालय, सीएम के आश्वासन पर खत्म हुआ आंदोलन

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

राजधानी शिमला की सील्ड रोड पर अधिवक्ताओं के वाहनों को रोके जाने का विवाद मंगलवार को उस समय बड़ा आंदोलन बन गया, जब प्रदेश हाईकोर्ट के सैंकड़ों वकील सड़क पर उतर आए। पहले मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर और फिर सचिवालय का घेराव करते हुए अधिवक्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सचिवालय के बाहर सड़क पर धरना देने से सर्कुलर रोड पर लंबा जाम लग गया और राजधानी की रफ्तार कई घंटों तक थम गई।

जाम का असर केवल दफ्तरों तक सीमित नहीं रहा। सरकारी कर्मचारी, स्थानीय लोग, पर्यटक और स्कूलों से लौट रहे बच्चे भी वाहनों की लंबी कतारों में फंस गए। शहर के कई हिस्सों में यातायात प्रभावित रहा और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी का सामना करना पड़ा। अधिवक्ताओं का आरोप था कि वर्षों से वे छोटा शिमला-सचिवालय-हाईकोर्ट मार्ग का उपयोग करते रहे हैं, लेकिन अब पुलिस उनकी गाड़ियों को रोक रही है और उन्हें कार्ट रोड से जाने के लिए कहा जा रहा है। उनका कहना है कि कार्ट रोड पहले ही ट्रैफिक के भारी दबाव में है और इससे अदालत पहुंचने में देरी हो रही है। मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं होने पर प्रदर्शन और तेज हो गया। सचिवालय के बाहर वकील सड़क पर बैठ गए और वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा तथा अंग्रेजों का कानून नहीं चलेगा जैसे नारे लगाए। चालान, गाड़ियां रोकें और उठे समान नियमों के सवाल प्रदर्शन के दौरान मामला केवल वकीलों की आवाजाही तक सीमित नहीं रहा। जब पूर्व सांसद और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जिस वाहन में सवार थीं, वह सील्ड रोड से गुजर रहा था, तब प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं ने पुलिस से नियमों को सभी पर समान रूप से लागू करने की मांग की। वकीलों की आपत्ति के बाद पुलिस ने संबंधित वाहन का 1500 रुपये का चालान किया। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने शहर की एसडीएम की गाड़ी को भी कुछ समय के लिए रोक दिया। बार एसोसिएशन के एक पदाधिकारी ने कहा कि मंगलवार का धरना केवल वकीलों के परमिट का मुद्दा नहीं था, सरकार और प्रशासन को यह बताने का प्रयास भी था कि सील्ड रोड पर अधिवक्ताओं के नाम की आड़ में कई अन्य वाहन भी चल रहे हैं। उनका कहना था कि यदि नियम लागू किए जा रहे हैं तो वे सभी पर समान रूप से लागू होने चाहिए।

उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान कई ऐसे वाहनों की पहचान करवाई गई जिनके पास वैध परमिट नहीं थे और उनके चालान भी करवाए गए। सीएम से वार्ता के बाद खत्म हुआ आंदोलन, कमेटी बनाकर परमिट देने का आश्वासनघण्टों चले गतिरोध का अंत बाद दोपहर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह और अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक के बाद हुआ।

ज्वालामुखी में मरीन कमांडो की सड़क हादसे में मौत, सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार

एजेंसी (हि.स.)
धर्मशाला

कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी पुलिस थाना के तहत एक सड़क हादसे में नौसेना में तैनात एक जवान की मौत हो गई। मृतक अमित सिंह राणा (32) भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो थे और उनकी बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किए जा चुके हैं। यह हादसा ज्वालामुखी क्षेत्र के खुंडिया के लाहड़ू में सोमवार देर रात हुआ, जब उनकी कार लगभग 500 फीट गहरी खाई में जा गिरी। पुलिस जिला देहरा के एसपी मयंक चौधरी ने घटना की पुष्टि की है।

पुलिस के अनुसार अमित राणा देर रात अपने एक दोस्त से मिलकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान लाहड़ू के खतरनाक मोड़ पर उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। यह हादसा रात करीब 11 बजे हुआ। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद करीब 12 बजे उन्हें खाई से बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें खुंडियां अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार वहीं मंगलवार को उनके पैतृक गांव में मृतक अमित राणा का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। ज्वालामुखी के विधायक संजय रत्न ने इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त किया है। अमित सिंह राणा 2 बहनों के इकलौते भाई थे। उनके परिवार में माता-पिता, पत्नी और एक 4 साल का मासूम बेटा है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दुश्मनों के बीच घुसकर किया था सफाया अमित राणा की बहादुरी की गाथा हर किसी को गर्व से भर देती है। वर्ष 2018 में जम्मू-कश्मीर में 'ऑपरेशन रक्षक' के तहत तैनाती के दौरान उन्होंने कई बड़े आतंकवाद विरोधी अभियानों में हिस्सा लिया। बेहद जोखिम भरे हालात में उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर आतंकियों के ठिकानों पर सटीक कार्रवाई की।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगीः तनवीर सादिक

श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने मंगलवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार स्थिर है और अपना पूरा पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राजनीतिक अस्थिरता के दावों को सपना बताकर खारिज कर दिया। जादिबल से विधायक ने कहा कि व्यापक राजनीतिक एकता के संबंध में कोई भी निर्णय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में कल होने वाली बैठक के बाद लिया जाएगा। सादिक ने कहा कि गुपकार समूह एकजुट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भी सरकार नहीं छोड़ी, अन्य लोगों ने ऐसा किया। हम कल इस पर चर्चा करेंगे। भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि जब पार्टी परिवारों को राजनीतिक चर्चा में घसीटती है तो यह गिर जाती है। उन्होंने कहा कि भाजपा भ्रम पैदा करने की आदी है। जनता ने हमें पांच साल का जनादेश दिया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कार्यकर्ता-आधारित पार्टी है। कोई भी नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं छोड़ रहा है। सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। जम्मू में चल रही तोड़फोड़ की कार्रवाई का जिक्र करते हुए सादिक ने चिंता व्यक्त की और आरोप लगाया कि केवल मुस्लिम संपत्तियों को ही निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह एक सोची-समझी साजिश प्रतीत होती है। इस पर कल की बैठक में चर्चा होगी। हमारा एजेंडा जन कल्याण है और जो भी निर्णय लिया जाएगा वह उनके हित में होगा।

गुणवत्तायुक्त शिक्षा ही समावेशी एवं दीर्घकालिक विकास का आधार : विक्रमादित्य सिंह

एजेंसी (हि.स.)
सोलन

लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि गुणवत्तायुक्त शिक्षा ही समावेशी और दीर्घकालिक विकास की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश के सबसे अधिक साक्षर राज्यों में शामिल है, जिसका श्रेय प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉ. यशवंत सिंह परमार की दूरदर्शी सोच तथा विभिन्न समय पर रहे नेतृत्व के प्रयासों को जाता है।

विक्रमादित्य सिंह मंगलवार को सोलन स्थित प्रतिष्ठित दी लॉरेंस स्कूल, सनावर के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दी लॉरेंस स्कूल, सनावर अपनी समृद्ध शैक्षणिक परंपरा और उत्कृष्ट पठन-पाठन के लिए देशभर में जाना जाता है। यहां के विद्यार्थियों ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर विद्यालय और प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने विकास के सभी मानकों पर एक आदर्श हिमाचल की परिकल्पना की थी और वह उस सपने को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ-साथ समाज सेवा को भी अपना ध्येय बनाएं।

उन्होंने कहा कि वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इस अवसर पर विक्रमादित्य सिंह ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया।

चार साल बाद कांगड़ा घाटी में रेल सेवा बहाल

सांसद अनुराग ठाकुर व डॉ. राजीव भारद्वाज ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी

एजेंसी (हि.स.)
धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में पिछले करीब चार साल से बंद पड़ी रेल सेवा मंगलवार से बहाल हो गई है। हिमाचल-पंजाब सीमा के साथ पठानकोट में चक्की रेल पुल के पुनर्निर्माण के चलते यह संभव हो पाया है जिससे रेल कनेक्टिविटी को दोबारा से नई उड़ान मिली है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर और सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने आज कांगड़ा रेलवे स्टेशन से नैरो गेज ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रेल सेवा का शुभारंभ किया।इस मौके पर कांगड़ा के विधायक पवन काजल और विधायक ठाकुर रणबीर सिंह निक्का, रेलवे के डीआरएम विवेक कुमार भी मौजूद रहे। सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार का लक्ष्य है कि हिमाचल के हर कोने को रेल सेवा से जोड़ा जाए। कांगड़ा की ये ट्रेन उसी संकल्प का हिस्सा है। नैरो गेज ट्रेन के शुरू होने से कांगड़ा-धर्मशाला क्षेत्र में पर्यटन को बड़ा बूस्ट मिलेगा। साथ ही स्थानीय लोगों को आवागमन की सुविधा और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 60 साल में गरीब को बस वोट बैंक बनाया। गौरतलब है कि वर्ष 2022 में बाढ़ के कारण हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर स्थित चक्की नदी रेलवे पुल बह जाने के कारण पठानकोट से कांगड़ा की ओर रेल सेवा पूरी तरह बाधित हो गई थी। चक्की नदी पर इस पुल के पुनर्निर्माण की मांग को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया गया जिस पर कार्यवाही करते हुए पुल के निर्माण का कार्य रेल मंत्रालय द्वारा शुरू कराया गया। करीब 70 करोड़ रुपये की लागत से बने नए पुल का निर्माण आधुनिक तकनीक से किया गया है। रेल सेवा की बहाली से देवभूमि में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। प्राकृतिक आपदा के लिए केंद्र से मांगे हैं 111 करोड़ अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के लिए केंद्र सरकार से 111 करोड़ की मांग कर रहे हैं। भाजपा संकट में साथ हर हिमाचली में साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 में देवभूमि हिमाचल प्रदेश को रेल नेटवर्क के विस्तार, आधुनिकीकरण, सुरक्षा परियोजना और विद्युतीकरण के लिए 2911 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। मोदी सरकार का हिमाचल में रेल नेटवर्क के विकास में सदा ही विशेष योगदान रहा है और यह मंजूर राशि कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई राशि से 27 गुना अधिक है।

अगर देवभूमि में मौजूदा रेलवे विस्तार के कार्यों को देखें तो अभी हिमाचल में 17 हजार 711 करोड़ की परियोजनाएं चल रहीं हैं जिससे राज्य में रेल नेटवर्क बेहतर होगा। 46 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल प्रदेश के चार रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन योजना के तहत नए सिरे से विकसित किए जाने का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। कांगड़ा से सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने कहा कि पहाड़ी राज्य में रेल नेटवर्क का विस्तार मतलब विकास की नई पटरी पर हिमाचल का आगे बढ़ना।

पहले महीनें में ही हांफ गई शराब का ठेका चलाने वाली तेलंगाना की कंपनी : जयराम

एजेंसी (हि.स.)
मंडी

पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि व्यवस्था परिवर्तन का राग अलापने वाली सुक्खू सरकार अपने दावे के अनुरूप आबकारी राजस्व में वृद्धि नहीं कर पाई है। आलम ये है कि जिन कंपनियों को शराब के यूनिट दिए गए हैं वो लाइसेंस फीस तक नहीं जमा कर पाये और विभाग को इनके ठेके सील करने पड़ रहे हैं।

मंडी से जारी प्रेस बयान में उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि कुल्लू-लाहौल और पांगी में शराब का ठेका चलाने का काम कांग्रेस शासित तेलंगाना की कंपनी को दिया गया था, लेकिन नियमों में फेर-बदल करके हिमाचल के सर्वाधिक पर्यटकों की आमद वाले कुल्लू-लाहौल-पांगी क्षेत्र के ठेकों को एक ही यूनिट के रूप में नीलाम किया गया और बेस प्राइस से मात्र एक लाख रुपए अधिक की बोली लगाकर एपीटको ने यह नीलामी अपने नाम की थी, मगर यह कंपनी पहले महीने में ही हांफ गई है और मई महीने की 15 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस न चुकाने के कारण प्रशासन द्वारा शराब के ठेके सील कर दिए गए हैं, जिससे साफ है कि जब टूरिस्ट सीजन के चरम पर यह स्थिति है तो आने वाले समय में कितनी भयावह स्थिति बनेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि इसके पहले भी हिमाचल प्रदेश में नगर निगम समेत विभिन्न निगमों और बोर्ड्स से मुख्यमंत्री ने शराब बिकवाकर उनका करोड़ों का घाटा करवाया है और अब वे आबकारी विभाग को अपने व्यवस्था परिवर्तन की प्रयोगशाला बनाकर प्रदेश के राजस्व को भारी चपत लगा रहे हैं क्योंकि जमीनी हकीकत और डॉक्युमेंटेड आंकड़े बताते हैं कि राज्य सरकार राजस्व बढ़ाने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है।

हिमाचल में चार दिन आंधी, बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश में जून की शुरूआत के साथ मौसम सुहावना बना हुआ है और भीषण गर्मी का असर कम है। मंगलवार को राज्य के अधिकांश इलाकों में दिनभर बादल छाए रहे, जबकि कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की गई।

मौसम विभाग ने अब 3 से 6 जून तक लगातार चार दिन प्रदेश के कई जिलों में आंधी, गर्जन, बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है।विभाग के अनुसार 3 से 7 जून तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहेगा और कई क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं।पिछले 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश हुई। सबसे अधिक 26 मिलीमीटर वर्षा सोलन जिले के कंडाघाट में दर्ज की गई। वहीं शिमला जिले के पर्यटन स्थलों कुफरी और फागू में 16-16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश और बादलों के असर से प्रदेश के कई क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई और गर्मी से राहत मिली है।मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 3 जून को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं का येलो अलर्ट रहेगा। इस दिन ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में आंधी, बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं की चेतावनी जारी की गई है।

एकता विविधता में एकता ही हमारे देश की सबसे बड़ी ताकतः कविन्द्र गुप्ता

'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' एकजुट, समृद्ध और सौहार्दपूर्ण देश की परिकल्पनाः राज्यपाल

कहा, संस्कृतियों और भाषाओं का मिलन ही देश को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान देता है

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने मंगलवार को लोक भवन में आयोजित तेलंगाना स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता की। यह कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत आयोजित किया गया। राज्यपाल ने कहा कि यह राष्ट्रव्यापी पहल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने तथा भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरम्भ की गई है। इस अवसर पर राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि विभिन्न राज्यों के स्थापना दिवस मनाने से उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं तथा राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को पहचानने और सम्मानित करने का अवसर प्राप्त होता है।

उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम नागरिकों के बीच भाईचारे, एकता और देशभक्ति की भावना को मजबूत करते हैं तथा उन लोगों के प्रयासों और बलिदानों को स्मरण करने का अवसर प्रदान करते हैं, जिन्होंने अपने-अपने राज्यों के गठन और विकास के लिए कार्य किया। कविन्द्र गुप्ता ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत एक दूरदर्शी पहल है, जिसका उद्देश्य एकजुट, समृद्ध और सौहार्दपूर्ण भारत का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम लोगों को देश की विविधता को समझने और उसका सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है तथा राष्ट्रीय एकता की भावना को और सुदृढ़ करता है। राज्यपाल ने कहा कि भारत भाषाओं, संस्कृतियों, परंपराओं और रीति-रिवाजों की अपार विविधता वाला देश है, जिसकी एकता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा कि लोग भले ही अलग-अलग राज्यों, समुदायों, जातियों या धर्मों से संबंधित हों लेकिन उनकी पहली पहचान भारतीय होने की है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों में एकता, सद्भाव, पारस्परिक सम्मान और राष्ट्रीय गौरव का संदेश निरंतर प्रसारित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना नागरिकों को देश की सामूहिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एकजुट होकर कार्य करने तथा एक मजबूत और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इस अवसर पर राज्यपाल ने समारोह से जुड़े तेलंगाना के नागरिकों को सम्मानित भी किया।

संक्षिप्त-समाचार

जल शक्ति विभाग में कार्यरत महिला ने फंदा लगाकर दी जान, पति व सास के खिलाफ मामला दर्ज

धर्मशाला। धर्मशाला में जल शक्ति विभाग में आउटसोर्स पर कार्यरत 45 वर्षीय महिला ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से ठीक पहले वह अपनी जुड़वां बहन जूली से फोन पर बात कर रही थीं। पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें मृतका ने ससुराल पक्ष की प्रताड़ना, पति द्वारा चरित्र पर शक करने और आर्थिक तंगी का जिक्र किया है। पुलिस को मिले सुसाइड नोट में मृतका ने 14 मुख्य बिंदुओं के माध्यम से अपनी आपबीती बताई है। उन्होंने लिखा कि 2006 में उनकी शादी हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद ही उनका जीवन कष्टमय हो गया। सुसाइड नोट के अनुसार मृतका के पति और ससुराल वाले उनके मायके जाने या किसी से भी बात करने पर शक करते थे। उन्होंने लिखा कि शक की सनक इस कदर थी कि मेरी इंसानियत आहत हो चुकी थी। मृतका ने यह भी आरोप लगाया कि उनके पति ने कभी अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझीं। वे अपनी मां के साथ रहते थे और उन्हें और उनके बेटे को अलग मकान में रहने के लिए छोड़ दिया था। पति छोटी-छोटी बातों पर भी लड़ाई-झगड़ा किया जाता था। कोर्ट द्वारा तय किया गया गुजारा भत्ता भी पति नहीं दे रहा था। यहां तक कि बच्चे को मां द्वारा दिए गए सामान का इस्तेमाल भी नहीं करने दिया जाता था। मृतका आर्थिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी। सुसाइड नोट के आधार पर पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाएगा।

कठुआ में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आठवें दिन भी जारी, उमर सरकार का पुतला फूंका

कठुआ। नगर परिषद कठुआ के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल मंगलवार को आठवें दिन भी जारी रही। इस दौरान कर्मचारियों ने मुखर्जी चौक पर जम्मू-कश्मीर की उमर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन कर अपना रोष प्रकट किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि वे पिछले आठ दिनों से लगातार हड़ताल पर बैठे हैं लेकिन सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि सभी सफाई कर्मचारियों को नियमित (पक्का) किया जाए वेतन में बढ़ोतरी की जाए और ठेकेदारी प्रथा को पूरी तरह समाप्त किया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि मात्र 9000 रुपये मासिक वेतन में परिवार का गुजारा करना मौजूदा महंगाई के दौर में बेहद कठिन हो चुका है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन देकर हड़ताल खत्म करवा दी जाती है लेकिन इस बार वे बिना मांगें पूरी हुए पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने साफ कहा कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। वहीं, कर्मचारियों ने यह भी चिंता जताई कि आगामी दिनों में बाबा अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, जिससे पहले ही शहर और आसपास के इलाकों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें खुद इस स्थिति पर दुख है, लेकिन सरकार और प्रशासन की अनदेखी के चलते वे मजबूर हैं। उन्होंने आगाह किया कि यदि जल्द उनकी मांगों को नहीं माना गया तो इसका असर अमरनाथ यात्रा पर भी पड़ सकता है।

'महंगाई डायन खाए जात है' की गूंज-कठुआ में कांग्रेस का अनोखा विरोध, गानों के जरिए केंद्र पर निशाना

कठुआ। बढ़ती महंगाई और अन्य जनहित मुद्दों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी कठुआ ने मंगलवार को एक अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष पंकज डोगरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता शहीदी चैक कठुआ में एकत्रित हुए और फिल्मी गीतों के माध्यम से केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकताओं ने ह्लमहंगाई डायन खाए जात हैह्व जैसे गीत गाकर सरकार पर तीखा तंज कसा और आम जनता की परेशानियों को उजागर किया। इस मौके पर पंकज डोगरा, युवा नेता रॉबिन शर्मा और अन्य कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद से लगातार महंगाई बढ़ रही है जिससे आम जनता पर भारी आर्थिक बोझ पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी टैक्स वसूला जा रहा है, जबकि यदि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी कम कर दे तो पेट्रोल 75 और डीजल 65 प्रति लीटर तक मिल सकता है। नेताओं ने यह भी कहा कि बढ़ती बेरोजगारी के चलते युवा वर्ग निराश होकर नशे की ओर बढ़ रहा है जो गंभीर चिंता का विषय है। कांग्रेस कार्यकताओं ने उज्ज्वला योजना पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि शुरूआत में मुफ्त गैस कनेक्शन देने के बाद अब सिलेंडर की कीमतें 1000 तक पहुंच गई हैं जिससे गरीब परिवारों के लिए गैस भरवाना मुश्किल हो गया है ।कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी देशभर में महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रही है और लोगों से अपील की कि वे एकजुट होकर इस महंगाई के संकट खिलाफ खड़े हों, ताकि आम जनता को राहत मिल सके।

श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक अक्तूबर से 15 दिनों के लिए सभी उड़ानें रहेंगी निलंबित

श्रीनगर। श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 1 अक्टूबर से 15 दिनों के लिए सभी उड़ानें निलंबित रहेंगी, ताकि रनवे की महत्वपूर्ण मरम्मत और रखरखाव का काम किया जा सके। दो सप्ताह के इस संचालन बंदी से जम्मू और कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र को भारी झटका लगने की आशंका है, क्योंकि यह दुर्गा पूजा के व्यस्त त्योहारों के मौसम से सीधे टकरा रहा है। इस दौरान घाटी में पारंपरिक रूप से पश्चिम बंगाल से भारी संख्या में पर्यटक आते हैं और ट्रैवल ऑपरेटरों को डर है कि इससे भारी वित्तीय नुकसान होगा। हवाई अड्डे के अधिकारियों के अनुसार पूर्ण बंद से पहले चरणबद्ध रखरखाव कार्य शुरू किया जाएगा। जुलाई से हवाई अड्डे का संचालन हर हफ्ते दो दिनों के लिए बंद रहेगा।

दैनिक सिटी दर्पण
आईना सच का
न्वोन्मेषकः स्व. कृष्णा शर्मा
स्व. गीता शर्मा
संस्थापकः स्व. सतपॉल शर्मा
स्वामी, प्रकाशक मुद्रक एवं संपादक भूपिंद्र शर्मा द्वारा इंप्रेशन्ज प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं. 22, ग्राउंड फ्लोर, फेस-2, इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकूला-134113 (हरियाणा) पर मुद्रित एवं 801/1, सेक्टर 40ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित-160036
सभी विवादों का केंद्र न्यायालय चंडीगढ़ होगा।
स्थानीय कार्यालय
801/1, सेक्टर-40ए, चंडीगढ़।
संपर्कः 7888450261
Email: citydarpan1@gmail.com

हरियाणा की चीनी मिलों को एक साल में घाटे से लाभ में लाना सुनिश्चित करें: नायब सिंह सैनी

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विजन-2047 के तहत सहकारिता विभाग के अगले 5 साले के रोडमैप व कार्ययोजना की समीक्षा बैठक में दिए विस्तृत दिशा-निर्देश

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की सभी सहकारी चीनी मिलों की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए इन्हें अगले एक साल में घाटे से निकालकर लाभ की स्थिति में लाना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए उच्चाधिकारी एक-एक मिल की स्थिति की गहन समीक्षा करें और सभी कमियों को दूर करें। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने यह निर्देश मंगलवार को हरियाणा सिविल सचिवालय में हरियाणा विजन-2047 के तहत सहकारिता विभाग के अगले 5 साल के रोडमैप व कार्ययोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। उन्होंने कहा कि वे तीन माह बाद विभाग की कार्य योजना की पुनः समीक्षा करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की सहकारी चीनी मिलों से किसानों के हित जुड़े हैं इसलिए इनका लाभकारी स्थिति में होना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जब हरियाणा में निजी चीनी मिले लाभ की स्थिति में चल रही हैं तो फिर सहकारी चीनी मिलें घाटे में क्यों चल रही हैं। सरकार ने इस साल चीनी मिलों को 632 करोड़ रुपये की सहायता दी है। उन्होंने सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव श्री पंकज यादव को सहकारिता विभाग की कार्यप्रणाली और मानव संसाधन का गहन विश्लेषण करते हुए विभाग का पूर्ण रूप से कायाकल्प करने को कहा। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि सहकारी चीनी मिलों में बैठे निठल्ले अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने समय-समय पर मिलों को अपडेट करने तथा एथनोल प्लांट्स लगाने के संबंध में भी व्यापक निर्देश दिए।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अगले वित्त वर्ष तक सभी सहकारी मिलों में कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने का उद्देश्य भी पूरा किया जाए। अधिकारियों ने बताया कि सहकारी मिलों में कार्यकुशल कर्मचारियों की कमी है, क्योंकि कई कार्यों से संबंधित पढ़ाई केवल पुणे या कानपुर में होती है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चीनी मिलों को कुशल युवा उपलब्ध करवाने के लिए आईटीआई में इससे संबंधित कोर्स शुरू करवाए जाएंगे। उन्होंने गन्ना बेचने आए किसानों का प्रतीक्षा समय कम होने पर संतुष्टि जाहिर की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य की जरूरतों के मद्देनजर प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भी कार्ययोजना तैयार की जाए। इसके लिए उन्होंने नई डेयरी को-ओपरेटिव सोसायटी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को डेयरी शुरू करने व हरा चारा उगाने के लिए पंचायत की जमीन लीज पर दी जाए। इसके लिए उन्होंने पंचायत विभाग, पशुपालन विभाग तथा सहकारिता विभाग की संयुक्त कार्ययोजना तैयार करने को कहा। उन्होंने प्रदेश में पशुधन के लिए भविष्य में हरे व सूखे चारे की समुचित उपलब्धता के लिए भी व्यापक योजना बनाने के निर्देश दिए।

श्री नायब सिंह सैनी ने हरको बैंक में 100 प्रतिशत पैक्स को कम्प्यूटरीकृत करने के निर्देश देते हुए सहकारी बैंकों में महिलाओं के खातों की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि सहकारी बैंकों में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 15 हजार खाते हैं जिन्हें बढ़ाने के प्रतिवर्ष के लक्ष्य रखे गए हैं। स्वयं सहायता समूहों व ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप की महिलाओं को क्रेडिट सुविधा प्रदान की गई है और 145 करोड़ रुपये का ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने लेबर एंड कंस्ट्रक्शन फेडरेशन के कार्यों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि कुछ सोसायटीज को अधिक ऋण देने की बजाय अधिक सोसायटीज को ऋण उपलब्ध करवाया जाए ताकि अधिक लोगों को लाभ मिले। इसके लिए नियमों को लचीला बनाया जाए। अधिकारियों ने बताया कि अभी 3000 सोसायटीज के माध्यम से 2000 करोड़ रुपये के कार्य करवाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अन्य संबंधित विभागों के समन्वय के साथ लक्ष्यों की प्राप्ति की योजना बनाई जाए। सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने ऋण वितरण का दायरा 130 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये करने तथा कम से कम 100 पैक्स को इसी साल लाभ की स्थिति में लाने के निर्देश दिए।

अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा को-ओपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के परिवारों के लिए आवास बनाने हेतु प्रति परिवार 12.50 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इस पर संबंधित परिवार को 7 प्रतिशत साधारण ब्याज अदा करना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कम आय वर्ग के ऐसे परिवारों को राहत देने के लिए ब्याज की दर को 7 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया जाए। इनके अलावा मुख्यमंत्री ने हरकोफैड, हैफेड व रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसायटी सहित सहकारिता विभाग के अंतर्गत आने वाले अन्य उपक्रमों के कार्यों व भविष्य की योजनाओं की भी समीक्षा की तथा अगले 5 वर्षों में इनकी कायापलट के संबंध में अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव पंकज यादव, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की प्रधान सचिव श्रीमती अमनीत पी कुमार, मुख्यमंत्री के ओएसडी व स्वर्ण जयंती हरियाणा राजकोषीय प्रबंधन संस्थान के महानिदेशक डॉ. राज नेहरू तथा मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री यशपाल यादव सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

कुरुक्षेत्र में हरियाणा राजस्व प्रशिक्षण अकादमी को मंजूरी

हरियाणा के राजस्व प्रशासन को आधुनिक बनाने और संस्थागत क्षमता निर्माण को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र जिले के गांव उमरी में 'हरियाणा राजस्व प्रशिक्षण अकादमी' की स्थापना को मंजूरी दे दी है। लगभग 100 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 14 एकड़ भूमि पर इस परियोजना को विकसित किया जाएगा। यह अकादमी राज्य के राजस्व अधिकारियों और फील्ड स्तर के कर्मचारियों के लिए एक प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र के रूप में काम करेगी। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तीय आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि यह अकादमी राजस्व अधिकारियों की पेशेवर क्षमताओं को बढ़ाने और उन्हें भूमि प्रशासन, आपदा प्रबंधन तथा सार्वजनिक सेवा वितरण की बदलती चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह निर्णय राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अकादमी के लिए एक उपयुक्त स्थान की पहचान करने हेतु की गई विस्तृत चर्चा के बाद लिया गया है, जिसकी घोषणा हरियाणा बजट 2026-27 में की गई थी। कुरुक्षेत्र जिले से प्राप्त कई प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के बाद सरकार ने इस परियोजना के लिए ग्राम पंचायत उमरी को सबसे उपयुक्त स्थान के रूप में चुना है। डॉ. मिश्रा ने बताया कि उमरी में प्रस्तावित स्थल के कई राजनीतिक और प्रशासनिक लाभ हैं।

गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया में एससी कैटेगरी के साथ छलावा: पंकज डावर

एजेंसी (हि.स.)
गुरुग्राम

एससी कैटेगरी के पद पर जनरल श्रेणी की नियुक्ति की तैयारी

कांग्रेस के जिला अध्यक्ष (शहरी) पंकज डावर ने कहा कि गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में मीडिया विभाग में होने जा रही प्रोफेसर की नियुक्ति में नियम, कायदों का पालन नहीं हो रहा। जिस पद पर एससी कैटेगरी के उम्मीदवार की नियुक्ति होनी चाहिए, उस पद पर जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार को लगाने की तैयारी हो रही है। यह यूनिवर्सिटी के नियमों का तो उल्लंघन है ही, साथ ही एससी कैटेगरी के साथ अन्याय है। संविधान की भी इसमें धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आरक्षण नीति का खुलकर उल्लंघन है। पंकज डावर ने मंगलवार को यहां जारी बयान में कहा कि गुरुग्राम यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से आगामी 04 जून 2026 को अपने मीडिया विभाग में प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए इंटरव्यू लेने की तैयारी है। पता चला है कि इस पद पर डा. राकेश योगी नामक शिक्षक की नियुक्ति लगभग तय मानी जा रही है। यूनिवर्सिटी में 08 जून 2026 को यूनिवर्सिटी की कार्यकारी परिषद (ईसी) की बैठक प्रस्तावित है। इसी बैठक में डा. राकेश योगी की नियुक्ति को मंजूरी मिलने की संभावना है। पंकज डावर ने कहा कि वे किसी व्यक्ति विशेष की खिलाफत की बात नहीं कर रहे, बल्कि नियमों के संभावित उल्लंघन की बात कर रहे हैं। अगर एससी पद पर डा. राकेश योगी की नियुक्ति होती है तो यह भी भ्रष्टाचार ही कहा जाएगा। सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने के लाख दावे करती है, मगर यहां भ्रष्टाचार खुलकर होने की संभावना है। पंकज डावर ने कहा कि मीडिया विभाग में यह पद पिछले करीब दो साल से लंबित रखा गया है। इतने लंबे समय तक किसी पद को भरने के लिए फिर से विज्ञापित करना चाहिए था।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कुरुक्षेत्र बाईपास प्रोजेक्ट के लिए हमेशा रखा जाएगा याद : सुभाष सुधा

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

हरियाणा के पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि कुरुक्षेत्र बाईपास कुरुक्षेत्र के हर नागरिक का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। इस ड्रीम प्रोजेक्ट को अमलीजामा पहनाकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को यहां के नागरिक हमेशा याद रखेंगे। इस बाइपास के लिए जल्द ही अब भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू होगा। यह बाईपास गांव इंदबडी, अमीन, किरमच, मथाना के आसपास से निकलेगा। इस बाईपास की लंबाई 27.9 किलोमीटर होगी।

पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र बाइपास स्थानीय नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा

प्रोजेक्ट है। इस बाइपास के बनने से ट्रेफिक जाम, सडक दुर्घटनाओं पर अंकुश लगने के साथ-साथ प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। इस प्रोजेक्ट के बनने से कुरुक्षेत्र को आर्थिक रूप से भी मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रयासों से ही कुरुक्षेत्र का चहुंमुखी विकास संभव हुआ है। मुख्यमंत्री की सोच के कारण ही कुरुक्षेत्र को पर्यटन, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। इस जिले के विकास पर लगभग 5000 करोड़ रुपए का बजट विभिन्न विभागों के माध्यम से छोटी व बड़ी परियोजनाओं पर खर्च किया जा चुका है। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रेलवे एलीवेटेड ट्रैक भी जल्द पूरा होने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रयासों की जितनी सराहना की जाए उतनी ही कम है।

पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से 200 बैड का नया नागरिक अस्पताल तैयार किया जा रहा है, 550 करोड़ रुपए की लागत से प्रथम चरण में आयुष यूनिवर्सिटी का कार्य शुरू किया जाएगा। इसके लिए टेंडर लग चुका है और हाई पावर परचेज कमेटी से अनुमति मिलने के बाद परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में सडकों, पीने के पानी, सीवरेज, एसटीपी आदि के प्रोजेक्ट पर तेज गति के साथ कार्य किया जा रहा है।

पूर्व राज्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र के नागरिकों की आशा के अनुसार और डिमांड के अनुरूप छोटी व बड़ी परियोजनाओं को अमलीजामा पहनाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 5 जून को आयुष यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे और यूनिवर्सिटी को विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देंगे।

संक्षिप्त-समाचार

अस्पताल के 19 स्टाफ सदस्यों के मोबाइल फोन हैक कर भेजे अश्लील मैसेज

गुरुग्राम। सोहना के नागरिक अस्पताल के कई स्टाफ सदस्यों के मोबाइल हैक करके उन पर अश्लील मैसेज भेजे गए। इस साइबर अटैक से अस्पताल के अधिकारियों, कर्मचारियों में हडकंप मच गया। हैकर्स का यह साइबर हमला सिर्फ डाटा चोरी तक नहीं था, बल्कि कर्मचारियों के मोबाइल हैक करके उन्हें अश्लील मैसेज भेजे गए। अस्पताल प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक इस डिजिटल सेंधमारी का शिकार हुए 19 कर्मचारियों के फोन में कई तरह की तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। कई कर्मचारियों के स्मार्टफोन पूरी तरह से फ्रीज या लॉक हो चुके हैं। जिन्हें वे चाहकर भी एक्सेस या ऑन नहीं कर पा रहे हैं। हैकर्स ने फोन में सेंध लगाकर डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का बेहद जरूरी और संवेदनशील विभागीय व व्यक्तिगत डेटा पूरी तरह गायब कर दिया है। इस हैकिंग का सबसे खतरनाक और परेशान करने वाला पहलू यह है कि हैकर्स इन हैक किए गए फोन नंबरों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पीड़ित कर्मचारियों के ही नंबरों से विभाग की महिला अधिकारियों और महिला सहकर्मियों को अश्लील व आपत्तिजनक मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। इससे कर्मचारियों की छवि तो खराब हो ही रही है, साथ ही अस्पताल के काम-काज के माहौल पर भी बुरा असर पड़ा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित कर्मचारियों ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों और साइबर क्राइम सेल को दी है।

कैथल में चरस समेत तीन तस्कर काबू

कैथल। जिला पुलिस द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ टीम ने एक तस्कर सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से एक किलो 84 ग्राम चरस (सुल्फा) बरामद की गई है। एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ प्रभारी एसआई मुकेश कुमार के नेतृत्व में टीम गश्त पर थी। गश्त के दौरान ब्रह्मानंद चौक पूंडरी पर गुप्त सूचना मिली कि गांव पाई निवासी राजू चरस बेचने का काम करता है और वह मोटरसाइकिल पर चरस लेने के लिए गांव करोडा गया हुआ है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने पाई-करोड़ा रोड पर नाकाबंदी कर दी। कुछ समय बाद संदिग्ध मोटरसाइकिल को आते देख पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने भागने का प्रयास किया। टीम ने तत्परता दिखाते हुए उसे काबू कर लिया। तलाशी के दौरान डीएसपी कलायत रोहताश कुमार की मौजूदगी में आरोपी राजू के पास से एक किलो 84 ग्राम चरस बरामद हुई। थाना पूंडरी में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह चरस उसे बालाजी कॉलोनी कैथल निवासी बंटी और मानस रोड पट्टी कोथ गामड़ी निवासी मोनू राम द्वारा सप्लाई की गई थी। पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सप्लायर बंटी और मोनू राम को भी गिरफ्तार कर लिया।

नारनौल में पत्नी और बेटी की हत्या के आरोप में किसान गिरफ्तार

नारनौल। जिले के नांगल चौधरी क्षेत्र के गांव ढाणी ठाकरान में एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी और नाबालिग बेटी की हत्या करने का आरोप लगा है। घटना के बाद पूरे गांव में शोक और सनसनी का माहौल है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव ढाणी ठाकरान निवासी अशोक सिंह का सोमवार शाम अपनी पत्नी राजबाला देवी (40) के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच शुरू हुई कहासुनी धीरे-धीरे तीखी बहस में बदल गई। इसी दौरान उनकी 14 वर्षीय बेटी मीनाक्षी अपनी मां का बचाव करने और दोनों के बीच विवाद शांत कराने के लिए पहुंची। आरोप है कि गुस्से में अशोक सिंह ने पत्नी और बेटी पर हमला कर दिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों की गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। दोहरे हत्याकांड की खबर फैलते ही गांव में लोगों की भीड़ जमा हो गई।

राहुल के उत्तराखंड दौरे की तैयारियों में जुटीं सैलजा

सिटी दर्पण संवाददाता
सिरसा

सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद, पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, उत्तराखंड प्रभारी एवं कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की सदस्य कुमारी सैलजा इन दिनों चार दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने 4 जून को प्रस्तावित नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे की तैयारियों को लेकर लगातार बैठकें कर कार्यक्रम की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। कुमारी सैलजा ने पौड़ी में कांग्रेसजनों एवं प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा, व्यवस्थाओं, जनभागीदारी, समन्वय तथा संगठनात्मक तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण संदेश देगा और इसे सफल, सुव्यवस्थित एवं ऐतिहासिक बनाने के लिए कांग्रेस संगठन पूरी तत्परता से कार्य कर रहा है। तैयारियों के क्रम में कुमारी सैलजा ने प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ पौड़ी स्थित कंडोलिया मैदान का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर की जा रही व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान मंच व्यवस्था, जनसभा स्थल, सुरक्षा, यातायात, कार्यकर्ताओं की भागीदारी तथा अन्य व्यवस्थाओं पर विशेष चर्चा की गई। बैठक में कार्यक्रम की सफलता के लिए संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां भी तय की गईं। सैलजा ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से समन्वित रूप से कार्य करते हुए कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया। इसके पश्चात सैलजा ने कंडोलिया देवता मंदिर में दर्शन एवं पूजा-अर्चना की तथा उत्तराखंड की समृद्धि, विकास, शांति और जनकल्याण की मंगलकामना की। प्रदेश की खुशहाली और जनता के कल्याण के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है तथा राहुल का दौरा जनता की आवाज को और मजबूती प्रदान करेगा।

सिलेंडर फिर महंगा, जनता पर बढ़ा महंगाई का बोझ

सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा सरकार ने एक बार फिर एलपीजी गैस की कीमतों में बढ़ोतरी कर आम लोगों और छोटे कारोबारियों पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। आज कमर्शियल एलसपीजी सिलेंडर की कीमत में 53.50 रुपये तथा पांच किलो वाले छोटू एलसपीजी सिलेंडर की कीमत में 11 रुपये की वृद्धि कर दी गई। बताया जा रहा है कि पिछले पांच महीनों में कमर्शियल एलसपीजी सिलेंडर की कीमत में कुल 1,571.50 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है, जबकि पिछले एक महीने में 5 किलो वाले छोटू सिलेंडर की कीमत 272 रुपये तक बढ़ गई है। कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि से छोटे व्यापारी, ढाबा संचालक, रेहड़ी-पटरी विक्रेता तथा निम्न एवं मध्यम वर्गीय परिवार सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। बढ़ती गैस कीमतों का सीधा असर रसोई के बजट और छोटे कारोबारों की लागत पर पड़ रहा है। विपक्षी दलों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने गैस की बढ़ती कीमतों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि महंगाई से पहले ही परेशान जनता पर यह अतिरिक्त बोझ है।

हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने तेलंगाना स्थापना दिवस पर दी शुभकामनाएं

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने तेलंगाना राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए कहा कि ह्यविकसित भारत 2047ह्व के संकल्प को साकार करने की दिशा में तेलंगाना और हरियाणा दोनों राज्य महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। राज्यपाल आज यहां हरियाणा लोक भवन में तेलंगाना स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों एवं तेलंगाना समुदाय के सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों सहित हरियाणा में निवास कर रहे तेलंगाना समुदाय के सदस्य उपस्थित रहे। प्रो. असीम कुमार घोष ने कहा कि 2 जून, 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन लाखों लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं की पूर्ति का ऐतिहासिक क्षण था। स्थापना के बाद से

तेलंगाना देश के सबसे गतिशील और प्रगतिशील राज्यों में से एक के रूप में उभरा है तथा कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और औद्योगिक विकास के क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लोगों की मेहनत, नवाचार और दृढ़ संकल्प ने राज्य को देश की आर्थिक प्रगति और तकनीकी विकास में अग्रणी योगदानकर्ताओं में शामिल कर दिया है। तेलंगाना की विकास यात्रा न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह भारत की लोकतांत्रिक एवं संघीय व्यवस्था की मजबूती को भी दर्शाती है।

इस अवसर पर हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजा शेखर वुंद्रू, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (मानवाधिकार एवं वाद-विवाद) डॉ. सी.एस. राव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डॉ. एम. रवि किरण, राज्यपाल के सचिव श्री विजयकुमार भाविकट्टी, राज्यपाल के एडीसी श्री धीरज सेतिया व श्री पी. भरत, अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा हरियाणा में निवास कर रहे तेलंगाना समुदाय के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

एसएफएस शिक्षकों के पद बजटेड किए जाएं तथा यूजीसी नियमों में विसंगतियां दूर की जाएं : कूटा

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (कूटा) ने हरियाणा केमाननीय मुख्यमंत्री से मांग की है कि विश्वविद्यालय मेंस्ववित्तपोषित योजना केअंतर्गत नियमित रूप से कार्यरत शिक्षकों के पदों को बजटेडपदों में परिवर्तित किया जाए तथा उच्च शिक्षा में लागू संशोधितयूजीसी नियमों की विसंगतियों को दूर किया जाए। कूटा के अध्यक्ष डॉ. जितेन्द्र कुमार एवं गैर-शिक्षक कर्मचारी संघकी प्रधान राजवंत कौर ने बताया कि वर्तमान में कुरुक्षेत्रविश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों एवं संस्थानों में लगभग 85 शिक्षक ल्लर्ा लगभग 250 गैर-शिक्षक कर्मचारियोंएसएफएस केअंतर्गत नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं। इन शिक्षकों का चयनभी बजटेड शिक्षकों की तरह निर्धारित योग्यता एवं चयनप्रक्रिया के माध्यम से किया गया है तथा वे पिछले लगभग दोदशकों से विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं शोध गतिविधियों मेंमहत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2005 में स्ववित्तपोषित योजना का उद्देश्यविश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करना तथारोजगारोन्मुख एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन करनाथा। वर्तमान में विश्वविद्यालय के 47 में से 13 विभाग एवंसंस्थान एसएफएस के अंतर्गत संचालित हैं, जिनमें लगभग5000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विधि, फार्मेसी, प्रबंधन, ललितकला, इंजीनियरिंग, जनसंचार एवं मीडिया तकनीक जैसे क्षेत्रोंके ये पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की भावना केअनुरूप विद्यार्थियों के रोजगार एवं कौशल विकास में महत्वपूर्णभूमिका निभा रहे हैं। कूटा ने कहा कि विश्वविद्यालय समीक्षा समिति, जिसकीअध्यक्षता प्रो. बृज किशोर कुठियाला ने की थी, ने अपनी 21 जुलाई 2011 की रिपोर्ट में पांच वर्ष से अधिक समय सेसफलतापूर्वक संचालित एसएफएस पाठ्यक्रमों को बजटेडकरने की सिफारिश की थी।

सरकारी अस्पतालों में साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को पीपीपी मोड पर करवाया जाएगा : आरती राव

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि प्रदेश सरकार का मुख्य फोकस राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़, सुरक्षित और आधुनिक बनाने पर है। आज चंडीगढ़ में अपने सरकारी आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में प्रबंधन को बेहतर करने के लिए साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर सौंपा जाएगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य अस्पतालों में महिला मरीजों, नर्सों, डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की सुरक्षा को बेहद मजबूत करना है।

स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के लोक नायक जयप्रकाश नागरिक अस्पताल में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामले का जिक्र करते हुए बताया कि आरोपी कंसलटेंट के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं।

आरती सिंह राव ने जानकारी दी कि चरखी दादरी जिले में निमार्णाधीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नाम देश के महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम के नाम पर रखा जाएगा। इस नामकरण के लिए उन्होंने केंद्र सरकार और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह इस नामकरण के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने जोर देकर कहा कि ऐसे प्रयासों से हमारी युवा पीढ़ी को देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के सर्वोच्च बलिदान और संघर्षों को करीब से जानने का अवसर मिलेगा। यह मेडिकल कॉलेज न केवल चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा, बल्कि युवाओं के लिए एक बड़ा प्रेरणा स्रोत भी बनेगा, जिससे वे देश सेवा के प्रति प्रेरित होंगे।

राज्य के नागरिकों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए आरती सिंह राव ने कहा कि सरकार की शीर्ष प्राथमिकता सभी जिलों में गायनेकोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिया और पीडियाट्रिशन (बाल रोग विशेषज्ञ) की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। उनका मुख्य फोकस सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में महिलाओं और बच्चों को उनके घर के नजदीक ही इलाज की सुविधाएं प्रदान करना है।

उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में चिकित्सा ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने करीब 104.16 करोड़ रुपये के विकास कार्य शुरू किए हैं। इसके साथ ही 15वें वित्त आयोग के तहत राज्य में 766 नए स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिसमें ग्रामीण और कस्बा स्तर पर स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करने के लिए 597 उप-स्वास्थ्य केंद्र, 51 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और 111 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ सेंटर शामिल हैं। मरीजों को आधुनिक सुविधाएं और सस्ती दवाएं देने के प्रयासों को रेखांकित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि हृदय रोगियों की सहूलियत के लिए राज्य के 600 स्वास्थ्य संस्थानों में टेली-ईसीजी सेवाएं शुरू की जा रही हैं। इसके अलावा आम जनता को सस्ती एवं उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध कराने के लिए 23 जिला अस्पतालों में 'अमृत फामेर्सी' स्थापित की गई हैं। इन फार्मेसियों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वे स्वयं भी समय-समय पर औचक निरीक्षण कर स्थिति का जायजा ले रही हैं।

पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक तकनीक को स्वास्थ्य क्षेत्र से जोड़ते हुए आरती सिंह राव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में ग्रीन एनर्जी को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी दिशा में अब सरकारी अस्पतालों में सोलर प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है, और हरियाणा सरकार भी इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए तेजी से कदम आगे बढ़ा रही है।

संपादकीय

सीबीएसई में जवाबदेही की घड़ी

शिक्षा व्यवस्था किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होती है और जब इस रीढ़ में भ्रष्टाचार या लापरवाही की आशंका घर कर ले, तो सरकार का सतर्क होना अनिवार्य हो जाता है। केंद्र सरकार ने 2 जून 2026 को ठीक यही किया। सीबीएसई के अध्यक्ष राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित कर दिया गया और साथ ही ऑन-स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद प्रक्रिया की जाँच के लिए एक जाँच समिति का गठन किया गया। यह निर्णय उस समय आया जब देशभर में लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों में रोष चरम पर था। दरअसल, विवाद की जड़ सीबीएसई की कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं में पहली बार बड़े पैमाने पर लागू की गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली यानी ऑन-स्क्रीन मार्किंग है। परिणाम घोषित होने के बाद जब छात्रों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रतियाँ देखने की कोशिश की, तो उन्हें धुंधली छवियाँ, गायब पृष्ठ और अधूरे खंड मिले। इतना ही नहीं, तकनीकी खामियाँ, भुगतान विफलताएँ और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया में देरी ने छात्रों और अभिभावकों को पारदर्शिता और जवाबदेही की माँग के लिए मजबूर कर दिया। यह मामला केवल एक तकनीकी विफलता नहीं, बल्कि व्यवस्थागत लापरवाही का प्रतीक है। जब किसी छात्र का पूरा भविष्य परीक्षा परिणाम पर निर्भर होता है और उसे यह भी नहीं पता कि उसकी उत्तर पुस्तिका सही तरीके से जाँची गई या नहीं, तो उसकी मानसिक पीड़ा की कल्पना करना भी कठिन है। सीबीएसई जैसे देश के सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड से इस स्तर की तकनीकी अव्यवस्था अत्यंत निराशाजनक है। विवाद का सबसे संवेदनशील पहलू है ऑन-स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद प्रक्रिया। जाँच के केंद्र में हैदराबाद स्थित कंपनी कोएम्प्ट एडुटेक है, जिसने तकनीकी मूल्यांकन में 100 में से 91 अंक प्राप्त कर और वित्तीय बोली में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से काफी कम दर पर बोली लगाकर यह ठेका हासिल किया था। ळउर को इस मूल्यांकन में 89 अंक मिले थे। इस चयन प्रक्रिया में तकनीकी मूल्यांकन का 70 प्रतिशत और वित्तीय बोली का 30 प्रतिशत भार था। सवाल यह उठता है कि जब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी अनुभवी और सुस्थापित कंपनी उपलब्ध थी, तो एक अपेक्षाकृत नई और कम ज्ञात कंपनी को इतना बड़ा और संवेदनशील ठेका किस आधार पर और किन परिस्थितियों में दिया गया? जाँच पैनल यह भी देखेगा कि क्या किसी विशेष विक्रेता को लाभ पहुँचाने के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों में ढील दी गई थी। जाँच समिति को अन्य विभागों के अधिकारियों की सहायता लेने का अधिकार दिया गया है और क्षमता निर्माण आयोग इसे सचिवीय सहायता प्रदान करेगा। समिति को एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सौंपनी होगी। यह समयसीमा तय करना सराहनीय है, क्योंकि इससे जाँच को लंबित रखने की परंपरागत प्रवृत्ति पर कुछ हद तक अंकुश लगेगा। अध्यक्ष और सचिव का स्थानांतरण एक कड़ा संदेश देता है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। परंतु स्थानांतरण मात्र कोई स्थायी समाधान नहीं है। असली जवाबदेही तब होगी जब जाँच समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, दोषियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई हो और प्रभावित छात्रों को समयबद्ध न्याय मिले। यह भी जरूरी है कि जाँच केवल खरीद प्रक्रिया तक सीमित न रहे, बल्कि इस पूरी डिजिटल प्रणाली की तकनीकी कमियों की भी गहन समीक्षा हो। डिजिटलीकरण की दिशा में कदम बढ़ाना समय की माँग है और ऑन-स्क्रीन मार्किंग जैसी प्रणालियाँ भविष्य में मूल्यांकन को अधिक पारदर्शी और कुशल बना सकती हैं। लेकिन इसके लिए किसी भी नई तकनीक को पायलट स्तर पर आजमाना, उसकी खामियाँ दूर करना और तब बड़े पैमाने पर लागू करना अनिवार्य है। लाखों बच्चों की परीक्षाओं पर अपरीक्षित तकनीक का प्रयोग करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं। सीबीएसई केवल एक परीक्षा बोर्ड नहीं, यह करोड़ों परिवारों की उम्मीदों और सपनों का केंद्र है। इस संस्था की विश्वसनीयता बनाए रखना हर सरकार और प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह जाँच महज औपचारिकता नहीं बनेगी, बल्कि इससे शिक्षा तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की एक नई संस्कृति का सूत्रपात होगा – जहाँ छात्र का हित सर्वोपरि हो।

युवा व उभरते खिलाड़ियों को आईपीएल दे रहा बड़े अवसर

मृत्युंजय दीक्षित (हि.स)

क्रिकेट के आईपीएल टी-20 का तूफान अगले सत्र तक के लिए शांत हो चुका है लेकिन 2026 आईपीएल की गहन समीक्षा जारी है। रजत पाटीदार के नेतृत्व वाली रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरू ने अपने गेंदबाजों और बल्लेबाजों के करिश्माई प्रदर्शन के चलते खिताब बचाने में सफलता प्राप्त की और लगातार दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी उठाई। एक बार फिर विराट कोहली जीत के नायक बने। आईपीएल-2026 में विराट ने अपने प्रदर्शन से उन आलोचकों को करारा उत्तर दिया जिन्होंने विराट को कई फॉर्मेट से संन्यास लेने के लिए मजबूर किया। विराट ने खेल के मैदान में एक बार फिर जता दिया कि लक्ष्य का पीछा करने में अभी भी उनका कोई सानी नहीं है और आज भी खेल की ऐसी स्थितियों के सबसे बड़े महारथी हैं। आईपीएल के फाइनल में विराट एक छोर पर डटे रहे और 42 गेंदों में 75 रन बनाकर अपनी टीम को जिताने में सफल रहे। शुभमन गिल के नेतृत्व वाली गुजरात टाइटंस को अपने ही मैदान में निराश होना पड़ा।

आईपीएल-2026 कई कीर्तिमानों व रोचक पलों के लिए याद किया जाएगा। आईपीएल- 2026 में कुछ नए सितारों का उदय हुआ, कुछ पुराने खिलाड़ियों ने अपनी टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करके लोगों का ध्यान आकर्षित किया।

वैभव रघुवंशीः बल्लेबाजी में राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय वैभव रघुवंशी ने अपने पहले ही पूरे सत्र में बेहद आक्रामक व तूफानी बल्लेबाजी से सभी को सम्मोहित करने मे सफलता प्राप्त की। सत्र की समाप्ति तक वैभव भारत के दुलारे बन गए। वैभव दो बार शतक के बेहद करीब आकर भी शतक बनाने से चूक गए नहीं तो एक यह रिकार्ड भी उनके नाम हो जाता। वैभव अपने पहले ही सत्र में ऑरेंज कैप अवार्ड जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। वैभव ने आईपीएल- 2026 में सबसे अधिक 776 रन बनाए और छक्कों के मामलों में वेस्टइंडीज के तूफानी क्रिस गेल का 14 साल पुराना 59 छक्कों का रिकार्ड ध्वस्त कर दिया। वैभव ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान चौकों-छक्कों की बारिश करते हुए कुल 63 चौके और 72 छक्के लगाए। वैभव ने 16 मैचों की 16 पारियों में 48.50 के औसत और 237.30 स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए। इनमें एक शतक तथा 5 अर्धशतक शामिल हैं।

दूसरे स्थान पर गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज कप्तान शुभमन गिल रहे जिन्होंने 732 रन बनाए और तीसरे नंबर पर गुजरात टाइटंस के ही बल्लेबाज साई सुदर्शन रहे जिन्होंने 722 रन बनाए और आईपीएल - 2026 में चमकदार बल्लेबाज बनकर उभरे। साई सुदर्शन भी क्रिकेट प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे। क्रिकेट कमेंटर्स, समीक्षक तथा विश्लेषकों ने साईं के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि वह आने वाले समय में भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का अहम हिस्सा हो सकते हैं।

आईपीएल से उभरे नए खिलाड़ियों में वैभव के लिए भारत की राष्ट्रीय टीम में शामिल होने का द्वार खुल गया है। वैभव को भारत-ए की टीम मे शामिल कर लिया गया है और उनका पहला विदेशी दौरा श्रीलंका की धरती से शुरू होगा जहां त्रिकोणीय श्रृंखला खेली जानी है। वैभव का नाम सितंबर-अक्टूबर में जापान मे आयोजित होने जा रहे एशियाई खेलों की क्रिकेट टीम में भी शामिल किया गया है। वैभव की अग्निपरीक्षा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व दक्षिण अफ्रीका के मैदानों पर होगी क्योंकि इन देशों की पिचें काफी तेज मानी जाती हैं।

वैभव, शुभमन और साईं के अलावा यशस्वी जायसवाल, राजस्थान के रियान पराग आदि ने भी अच्छा प्रदर्शन कर लोगों को आकर्षित किया।

गेंदबाजीः भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे बंगलुरू के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार सर्वाधिक 28 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज रहे और अपनी फिटनेस को साबित किया दूसरे नंबर पर ज्योफ्रा आर्चर रहे जिन्होंने अपनी टीम के लिए 25 विकेट लिए। इस लिहाज से देखें तो आईपीएल-2026 नए गेंदबाजों को तलाशने में नाकाम रहा। इस बार बल्लेबाज ही पूरे सत्र में छाए रहे। हार्दिक पांड्या जैसे गेंदबाजों के लिए यह सीजन बुरे सपने जैसा रहा।

नाम बड़े दर्शन छोटेः आईपीएल सीजन- 2026 में 10 महंगे खिलाड़ी लगभग 125 करोड़ में बिके लेकिन ये नाम बड़े और दर्शन छोटे की कहावत सिद्ध करने में लगे रहे। कोलकाता के कैमरून ग्रीन, चेन्नई के कार्तिक शर्मा, चेन्नई के ही प्रशांत वीर, राजस्थान के रवि विश्वनोई, दिल्ली के आकिब अली, लखनऊ के जोस इग्लिस, हैदराबाद के लिविंगस्टोन आदि खिलाड़ी पूरी तरह से नाकाम रहे।

आईपीएल-2026 में किसी भी टीम का कप्तान अपने घरेलू मैदानों पर अपने मन की पिच नही बनवा सका और न ही विजय प्राप्त कर सका। फाइनल मुकाबले में भी यह देखने को मिला, जहां अहमदाबाद में गुजरात को अपने ही स्टेडियम में हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ की टीम भी अपने ही मैदान में हारती चली गई। आईपीएल-2026 क्रिकेट प्रेमियों को कई यादगार अनुभव देकर विदा हुआ है, यह वैभव के साथ-साथ दूसरी उभरती प्रतिभाओं के लिए मार्ग खोल कर विदा हुआ है।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

आज का राशिफल

मेषः आज कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अनावश्यक बहस से बचना आपके हित में रहेगा। किसी पुराने विवाद या लंबित मामले के फिर से सामने आने की संभावना है। घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च बढ़ सकता है। *(सिटी दर्पण)*

वृषभः आज स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। विरोधियों या प्रतिस्पर्धियों को हल्के में लेने की भूल न करें। घर की व्यवस्था और साफ-सफाई में समय व्यतीत हो सकता है। बच्चों की भावनाओं और समस्याओं को समझने का प्रयास करें। *(सिटी दर्पण)*

मिथुनः नए कार्यों की शुरूआत के लिए दिन अनुकूल रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को उनके कार्यों के लिए सराहना और सम्मान मिल सकता है। साझेदारी में किए गए प्रयास लाभदायक साबित होंगे। परिवार में विवाह या रिश्तों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। *(सिटी दर्पण)*

कर्कः कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों के निर्देशों का पालन करना आवश्यक रहेगा। छोटी-मोटी बातों को नजरअंदाज करना बेहतर होगा। रहस्य, शोध या आध्यात्मिक विषयों के अध्ययन में रुचि बढ़ सकती है। विरोधियों के साथ भी संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा। *(सिटी दर्पण)*

सिंहः आपकी सकारात्मक आदतें और व्यवहार लोगों को प्रभावित करेंगे। सामाजिक और जनहित के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। छोटी समस्याओं या तनाव को मन पर हावी न होने दें। विद्यार्थी कुछ नया सीखने और अपनी प्रतिभा निखारने का प्रयास करेंगे। *(सिटी दर्पण)*

कन्याः आज अपनी प्रतिभा और क्षमताओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। कोई मित्र आपसे मिलने घर आ सकता है। विरोधियों की गतिविधियों पर नजर बनाए रखें। शेयर बाजार या निवेश से जुड़े मामलों में लाभ मिलने की संभावना है। *(सिटी दर्पण)*

तुलाः कार्यस्थल पर आपको नई जिम्मेदारी या उच्च पद प्राप्त हो सकता है। जीवनसाथी के साथ रोमांटिक और सुखद समय व्यतीत करेंगे। व्यक्तित्व में आकर्षण और आत्मविश्वास बढ़ेगा। अविवाहित लोगों के विवाह संबंध तय होने की संभावना है। *(सिटी दर्पण)*

वृश्चिकः वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। भूमि, भवन या अन्य अचल संपत्ति की खरीदारी का विचार बना सकते हैं। करीबी मित्रों और शुभचिंतकों का पूरा सहयोग मिलेगा। हालांकि अत्यधिक आत्मविश्वास नुकसान का कारण बन सकता है, इसलिए संतुलन बनाए रखें। *(सिटी दर्पण)*

धनुः आज आपका मन प्रसन्न और उत्साहित रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से राहत मिलने की संभावना है। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। मनचाहे कार्य पूरे होने से संतोष मिलेगा। *(सिटी दर्पण)*

मकरः आज योजनाएं आपकी अपेक्षा के अनुसार पूरी नहीं हो पाएंगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है। चिकित्सा और दवाइयों पर खर्च बढ़ने की संभावना है। *(सिटी दर्पण)*

कुंभः कार्यस्थल पर काम का दबाव अपेक्षाकृत कम रहेगा, जिससे राहत महसूस होगी। कला, साहित्य, संगीत या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को सम्मान प्राप्त हो सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में होती नजर आएंगी। *(सिटी दर्पण)*

मीनः आज आपका आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत रहेगा। प्रबंधन और नेतृत्व से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं। परिवार के साथ समय बिताने से संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार महसूस होगा। *(सिटी दर्पण)*

भारत और ओमान द्वारा एक नए आर्थिक गलियारे को गति

राजेश अग्रवाल

भारत और ओमान के बीच वाणिज्यिक रिश्ते सदियों से चलते आ रहे हैं। दोनों देशों का एक साझा इतिहास प्राचीन नावों के पाल पर सवार होकर आगे बढ़ता रहा है और पीढ़ियों से चले आ रहे सांस्कृतिक आदान-प्रदान के जरिए कायम रहा है। भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) इस सभ्यतागत बंधन को और मजबूत करता है। एक ऐसे दौर में जब वैश्विक व्यापार भू-राजनैतिक प्रतिद्वंद्विताओं, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और बढ़ते संरक्षणवाद से जूझ रहा है, यह समझौता भरोसेमंद साझेदारों के साथ आर्थिक जुड़ाव को गहरा करने के भारत के दृढ़ संकल्प को दशार्ता है। वर्ष 2022 में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ हुए ऐतिहासिक समझौते के बाद, यह सीईपीए खाड़ी देशों के साथ भारत की बढ़ती आर्थिक भागीदारी को मजबूती से स्थापित करता है।

द्विपक्षीय व्यापार में लगातार विस्तार हुआ है और वित्त वर्ष 2025-26 में यह 11.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। जबकि, सेवाओं का व्यापार 2024 में 863 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा। आर्थिक रिश्तों का विविधीकरण हुआ है और इसमें परंपरागत वस्तुओं से परे इंजीनियरिंग सामान, फार्मास्यूटिकल्स और आईटी सेवाओं का समावेश हुआ है। फिर भी, काफी अनछुई संभावनाएं अभी भी बाकी हैं। वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार, निवेश, पेशेवर आवाजाही और नियामकीय सहयोग को शामिल करके, यह सीईपीए अधिक सुदृढ़, समन्वित और व्यापक आर्थिक साझेदारी का एक व्यापक ढांचा तैयार करता है।

भारतीय निर्यात के विकास का प्रवेश द्वार

इस सीईपीए के तहत ओमान की 98.08 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर भारतीय निर्यात को शुल्क-मुक्त बाजार पहुंच हासिल है। इस समझौते से पहले, भारत के निर्यात का सिर्फ लगभग 15 प्रतिशत हिस्सा ही सर्वाधिक तरजीह वाले देश (मोस्ट फेवर्ड नेशन) की व्यवस्था के तहत ओमान में शुल्क-मुक्त प्रवेश करता था, जबकि शेष पर 5 प्रतिशत तक का शुल्क लगता था। इस सीईपीए के तहत, भारत के वर्तमान निर्यात की 99.38 प्रतिशत मात्रा अब शुल्क-मुक्त प्रवेश का लाभ उठाएगी।

भारतीय निर्यातकों की दृष्टि से, ये लाभ काफी महत्वपूर्ण हैं। ओमान के 'विजन 2040' के तहत बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक विविधीकरण में उसके द्वारा किए जा रहे निवेश से मांग में वृद्धि होगी। वित्त वर्ष 2024-25 में 875.83 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के इंजीनियरिंग सामानों के निर्यात के 2030 तक बढ़कर 1.3 से 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच होने का अनुमान है। शून्य शुल्क की सुविधा के जरिए वस्त्र एवं परिधान सेक्टर को क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों पर महत्वपूर्ण बढ़त मिलेगी। इससे तिरुपुर, सूरत, लुधियाना और कोयंबटूर जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी और साथ ही रोजगार भी सृजित होगा।

मौके व्यापक और विविध हैं। आयात पर निर्भर ओमान का दवा बाजार भारतीय कंपनियों के लिए मजबूत संभावनाएं पेश करता है। नियामकीय मंजूरियोंमें तेजी, गुणवत्ता प्रमाणपत्रों की मान्यता और प्रमुख उत्पादों के शुल्क-मुक्त पहुंच से अनुपालन संबंधी लागत में कमी आएगी और बाजार में पैठ बढ़ेगी। चावल, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, मसाले और कन्फेक्शनरी सहित कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण आधारित निर्यात को भी लाभ होगा।

खुलते बाजार, हितों का संरक्षण

भारत के हालिया व्यापार समझौतों के अनुरूप, इस सीईपीए में एक संतुलित और सुविचारित दृष्टिकोण का समावेश है। जहां एक ओर भारत प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने एवं वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल होने के लिए बाजारों को खोल रहा है, वहीं दूसरी ओर संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रहा है। दुग्ध तथा अनाज जैसे प्रमुख कृषि उत्पादों के साथ-साथ रबर, वस्त्र और जूते जैसे उद्योग सुरक्षित बने हुए हैं। यह दृष्टिकोण बाहरी बाजारों तक पहुंच और घरेलू कमजोरियों से बचाव को एक साथ जोड़ता है।

भारत ने ओमान से आयात होने वाले लगभग 95 प्रतिशत उत्पादों पर लागू होने वाली अपनी 77 प्रतिशत से अधिक टैरिफ लाइनों को उदार बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। इससे ओमान के प्रमुख निर्यातों, खासकर मेथनॉल और निर्जल अमोनिया जैसे औद्योगिक इनपुट को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा। ओमान को धातुओं और मिश्र धातुओं की एक विस्तृत श्रृंखला में तरजीही बाजार पहुंच हासिल होगी। इससे हमारे दोनों देशों को कम उत्पादन लागत का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।

जिन क्षेत्रों में भारत के रक्षात्मक हित हैं, उन क्षेत्रों में टैरिफ दर कोटा (टीआरक्यू) के जरिए ओमान को पहुंच प्रदान की गई है। यह व्यवस्था निर्दिष्ट मात्रा की सीमा के भीतर खजूर, संगमरमर और चुनिंदा पेट्रोकेमिकल जैसे उत्पादों के तरजीही निर्यात की अनुमति देती है। बेहद सावधानीपूर्वक तैयार किया गया जुड़ाव का यह तरीका प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के साथ-साथ संक्रमण काल के दौरान कमजोर क्षेत्रों को सहायता भी प्रदान करता है।

व्यापार, प्रतिभा और विश्वास

यह सीईपीए भारतीय सेवा प्रदाताओं को उन सभी क्षेत्रों में बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं प्रदान करता है, जहां भारत की स्थिति स्पष्ट रूप से मजबूत है। इनमें आईटी, पेशेवर सेवाएं और निर्माण क्षेत्र शामिल हैं। विभिन्न क्षेत्रों में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने वाले प्रावधानों के साथ, भारतीय कंपनियों को ओमान में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के अधिक मौके मिलेंगे।

प्रतिभाओं की दृष्टि से भी, यह समझौता एक बड़ी उपलब्धि है। कंपनी के भीतर स्थानांतरित कर्मचारियों (इंट्रा-कॉरपोरेट ट्रांसफरी) की सीमा को 50 प्रतिशत तक बढ़ाकर, भारतीय कंपनियों को अब विशिष्टता प्राप्त कर्मचारियों को आसानी से तैनात करने तथा बाजार में अपनी मजबूत उपस्थिति को और अधिक मजबूत करने की सुविधा मिल गई है। इसके अलावा, किसी भी मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) में पहली बार, ओमान ने स्वतंत्र पेशेवरों के लिए एक समर्पित आवाजाही की व्यवस्था स्थापित की है। अब जबकि वैश्विक स्तर पर जनसांख्यिकीय बदलावों के कारण कारखानों में श्रमिकों की कमी हो रही है और आधुनिक मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर एआई एवं रोबोटिक्स के साथ जुड़ रहा है, ऐसे में यह प्रावधान भारतीय प्रतिभाओं के लिए दुनिया भर में एक सशक्त मिसाल कायम करता है।

इस सीईपीए में समर्पित स्वास्थ्य सेवा का एक परिशिष्ट भी शामिल है, जो आयुर्वेद जैसी पारंपरिक प्रणालियों को मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवा में शामिल करने में सुविधा प्रदान करता है। साथ ही, यह चिकित्सा पेशेवरों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को भी सुव्यवस्थित करता है। इसके अलावा, एक अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा समझौते से संबंधित बातचीत से भविष्य में भारतीय प्रवासी समुदाय को दोहरे योगदान के बोझ से बचाया जा सकेगा।

क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण

भारत-ओमान सीईपीए नियामकीय सहयोग, सामंजस्यपूर्ण मानकों और अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रियाओं के जरिए गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करके टैरिफ से परे जाता है। यह भारत के आधुनिक व्यापार समझौतों से जुड़े उच्च मानकों को दशार्ता है और सीमा के भीतर मौजूद वाणिज्य में रुकावट डालने वाली विभिन्न बाधाओं को दूर करता है।

भारत एक बेहद ही एकीकृत क्षेत्रीय व्यापार संरचना की नींव रख रहा है। भारत के मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से जुड़े सभी साझेदार मिलकर अब वैश्विक जीडीपी का लगभग 67 प्रतिशत और वस्तुओं एवं सेवाओं के वैश्विक आयात का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा हैं। खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका और व्यापक हिंद महासागर क्षेत्र के मिलन बिंदु पर स्थित, ओमान को एक अनूठी भौगोलिक हैसियत हासिल है। सोहार, दुक्म और सलालाह जैसे ओमान के लॉजिस्टिक्स व औद्योगिक केन्द्र भारत की मैन्यूफैक्चरिंग संबंधी विशेषज्ञता एवं प्रतिभाओं को व्यापक मध्य पूर्व और अफ्रीका के साथ जोड़कर मूल्य श्रृंखलाओं को एकीकृत कर सकते हैं। इसका परिणाम क्षेत्रीय संपर्क और विकास के लिए निर्मित एक साझेदारी के रूप में सामने होगा।

व्यापार समझौते तभी सफल होते हैं जब वे भरोसा पैदा करते हैं, व्यवसायों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, श्रमिकों को नए कौशल हासिल करने के लिए प्रेरित करते हैं और अर्थव्यवस्थाओं को स्थायी साझेदारी बनाने के लिए आगे बढ़ाते हैं। यह सीईपीए ठीक यही काम कर रहा है। यह सदियों पुराने रिश्ते को इक्कीसवीं सदी की हकीकतों के अनुरूप एक रणनीतिक आर्थिक साझेदारी में परिवर्तित कर रहा है।

(लेखक वाणिज्य विभाग के सचिव हैं)

राजघाट से शांतिवन: कौन शामिल होते हैं सर्वधर्म प्रार्थना सभा में

विवेक शुक्ला (हि.स)

भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर 27 मई को सुबह उनकी समाधि शांतिवन में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इससे पहले ही वहां विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु, विद्वान और श्रद्धालु वहां पहुंचने लगे थे। इनमें अधिकांश वे चेहरे थे जो गांधी समाधि राजघाट पर 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को भी नियमित रूप से दिखाई देते हैं। ये सभी अपने-अपने धर्मो की पवित्र पुस्तकों से प्रार्थना के दौरान पाठ करते हैं।

गत दो-ढाई दशकों से शांतिवन और राजघाट पर बाइबिल का पाठ करने वाले जॉर्ज सोलोमन तुर्कमान गेट स्थित ट्रिनिटी चर्च में पादरी हैं। वे दिल्ली और हरियाणा के सोनीपत में सेंट स्टीफंस कैंब्रिज स्कूल की प्रबंधन समिति से भी जुड़े हैं। वे कहते हैं, 'भारत में सरकारी स्तर पर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन इस बात का प्रमाण है कि यह देश सबका है। बाइबिल भी प्रेम और भाईचारे का संदेश देती है।'

ये चेहरे वास्तव में भारत की आत्मा हैं, जहां विविधता में एकता जीवित है। सर्वधर्म प्रार्थना सभाएं हमें बार-बार याद दिलाती हैं कि गांधीजी का सपनों का भारत सबका है, जिसमें हर धर्म को सम्मान मिलता है।

मकसूद अहमद शांतिवन और राजघाट पर कुरान की आयतें पढ़ते हैं। वे पूर्व राष्ट्रपतियों के.आर. नारायणन, प्रणव मुखर्जी तथा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभाओं में भी शामिल हो चुके हैं। एंग्लो अरबी स्कूल में जीव विज्ञान के शिक्षक मकसूद अहमद कहते हैं कि कुछ दिमागी रूप से असंतुलित लोग इन सभाओं की भी आलोचना करने लगे हैं।

डॉ. बलदेव आनंद सागर 2 अक्टूबर और 30 जनवरी की विशेष तिथियों पर सर्वधर्म प्रार्थना में गीता पाठ करते हैं। वे बताते हैं कि पहली बार राजघाट पर इस सभा का हिस्सा बनने पर जो अनुपम अनुभूति हुई, वह आज भी उनके मन में ताजा है। राजघाट पर वे गीता के 5-6 श्लोक पढ़ते हैं, जबकि 30 जनवरी मार्ग पर पंचदेव-सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु-की प्रार्थना का पाठ करते हैं। वे मानते हैं कि सनातन परंपरा में इन सभी देवताओं की पूजा अनिवार्य है।

सर्वधर्म प्रार्थना का सुंदर विचार महात्मा गांधी ने विश्व को दिया था। उनके जीवनकाल में ही इसकी शुरूआत हुई और आज भी यह परंपरा पूरे जीवंत रूप में मौजूद है। इन सभाओं में बहाई, यहूदी, बौद्ध, जैन और सिख धर्मों के पवित्र ग्रंथों का भी पाठ किया जाता है। सर्वधर्म प्रार्थना का विचार अत्यंत व्यापक और महत्त्वपूर्ण है। यह संदेश देता है कि भारत में अलग-अलग धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ बैठकर अपने धर्मग्रंथों के मुख्य संदेशों को साझा कर सकते हैं। इन सभाओं में भाग लेने वालों को 5100 रुपए का मानदेय मिलता है।

जॉर्ज सोलोमन विभिन्न स्थानों पर आयोजित सर्वधर्म प्रार्थनाओं में बाइबिल का पाठ करते हैं। वे कहते हैं कि नरेन्द्र मोदी की सरकार भारत में सबके साथ समान व्यवहार करती है। सरकारी आयोजनों में इन सभाओं का होना भारत सरकार के समान धार्मिक रवैये का प्रमाण है। बाइबिल सहित सभी धर्मग्रंथ प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं। गांधीजी को दक्षिण अफ्रीका में बाइबिल और ईसाई धर्म को गहराई से समझने का अवसर मिला था।

85 वर्षीय कात्सू सान भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रार्थना सभाओं के अलावा 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को राजघाट तथा 30 जनवरी मार्ग (बिड़ला हाउस) पर आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभाओं की स्थायी उपस्थिति हैं। उन्होंने डॉ. शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायणन, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, प्रणव मुखर्जी, रामनाथ कोविंद जैसे राष्ट्रपतियों तथा इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के समक्ष बौद्ध धर्मग्रंथों से प्रार्थना पढ़ी है।

संसद के नये भवन के भूमिपूजन के समय भी सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी। इन सभाओं में प्रत्येक धर्म के प्रतिनिधि को 5-6 मिनट का समय दिया जाता है।

धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह कदापि नहीं है कि कोई देश अपनी धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक आस्थाओं को त्याग दे। यह असंभव भी है। भारत के संविधान की मूल प्रति में अर्जुन को गीता का उपदेश देते श्रीकृष्ण की तस्वीर है। भगवान बुद्ध शांति का उपदेश देते दिखते हैं। हिंदू धर्म के प्रतीक शतदल कमल, राम, कृष्ण, नटराज के चित्र भी वहाँ मौजूद हैं। यदि आज ये चित्र लगाए जाते तो कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी इन्हें सांप्रदायिक बताकर विरोध करते।

संविधान की मूल प्रति पर मुगल बादशाह अकबर, सिखों के दसवें गुरु गोविंद सिंह, मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान और 1857 की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के चित्र भी हैं। इससे स्पष्ट है कि भारत के लिए धर्मनिरपेक्षता के अर्थ बहुत गहरे हैं। बिना मतलब विवाद खड़े करने वालों को इसे समझना चाहिए। सर्वधर्म प्रार्थना सभाएँ भारत की साझा संस्कृति और समावेशी लोकतंत्र की सुंदर अभिव्यक्ति हैं। ये हमें याद दिलाती रहेंगी कि विविधता हमारी ताकत है और एकता हमारा संकल्प।

(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार और जाने-माने स्तंभकार हैं।)

तरुनप्रीत सिंह सौंद ने मनरेगा यूनियन से की मुलाकात समयबद्ध तरीके से मांगों के समाधान का दिया भरोसा

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

मनरेगा कर्मचारियों की मांगों एवं चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री स. तरुनप्रीत सिंह सौंद ने यहां पी.एस.पी.सी.एल. गेस्ट हाउस में मनरेगा कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनकी लंबित मांगों को शीघ्र एवं समयबद्ध तरीके से हल करने का भरोसा दिया।

स. सौंद ने विभाग के सचिव श्री अजित बालाजी जोशी तथा संयुक्त विकास आयुक्त-कम-कमिश्नर शैना अग्रवाल के साथ यूनियन प्रतिनिधियों की मांगों और मुद्दों को गंभीरता से सुना। उल्लेखनीय है कि राज्य भर में मनरेगा के अंतर्गत लगभग 2100 कर्मचारी कार्यरत हैं।

स. तरुनप्रीत सिंह सौंद ने मनरेगा कर्मचारियों द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा पंजाब के गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में इन कर्मचारियों की अहम भूमिका रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनकी जायज मांगों को समयबद्ध तरीके से हल करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मंत्री ने यूनियन प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी एवं गतिशील नेतृत्व में पंजाब सरकार मनरेगा कर्मचारियों के हितों की रक्षा और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी, कर्मचारी-हितैषी और जवाबदेह प्रशासन पर विश्वास रखती है तथा कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

पंजाब सरकार की जन-हितैषी नीति का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, सरकारी कर्मचारियों और ग्रामीण समुदाय सहित समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार समग्र विकास सुनिश्चित करने, ग्रामीण शासन को मजबूत करने, रोजगार के बेहतर अवसर पैदा करने तथा राज्य भर में नागरिक-केंद्रित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

इस दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के सचिव श्री अजित बालाजी जोशी ने भी प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि बैठक में उठाए गए सभी मुद्दों की संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर गहन जांच की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि नीतिगत निर्णयों और वित्तीय प्रभावों से जुड़े मामलों के व्यावहारिक एवं टिकाऊ समाधान हेतु वित्त विभाग से भी चर्चा की जाएगी।

बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों में यूनियन के सदस्य गुरसेवक सिंह, प्रेम सुखदास, गुरदीप दास, सुखप्रताप, दविंदर सिंह, अमरीक सिंह महिराज, रणजीत सिंह, अमृतपाल सिंह और संदीप कक्कड़ शामिल थे।

पंजाब सरकार स्टोरेज स्पेस के मुद्दे को हल करने के लिए पूरी तरह प्रयासरत

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा भंडारण स्थान(स्टोरेज स्पेस) के महत्वपूर्ण मुद्दे को हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, क्योंकि यह मुद्दा प्रदेश के खरीद कार्यों से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने आज यहां एक बैठक के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा समय-समय पर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी से कई बैठकें की गई हैं और उन्हें पंजाब में उचित भंडारण स्थान के मुद्दे से अवगत कराया गया है। मंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार हमेशा खरीद प्रक्रिया से जुड़े सभी भागीदारों के हितों को ध्यान में रखती है और इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष पुनः उठाने में कोई देरी नहीं की जाएगी। मंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश के पास 181 लाख मीट्रिक टन (एल.एम.टी.) भंडारण स्थान उपलब्ध है, लेकिन भंडार किये गए अनाज की मात्रा 190 एल.एम.टी. है, जो कुल भंडारण स्थान का 105 प्रतिशत है। श्री कटारूचक्क ने बताया कि प्रदेश के पास चावल का पिछला स्टॉक 37.76 एल.एम.टी. है, जबकि गेहूं का स्टॉक 40 एल.एम.टी. है। उन्होंने आगे कहा कि हालातों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश से हर महीने कम से कम 10 एल.एम.टी. चावल और 10 एल.एम.टी. गेहूं की लिफ्टिंग करना अनिवार्य है और इस संबंध में अगले 4 महीने अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने यह भी दोहराया कि पंजाब मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए कृषि क्षेत्र से संबंधित हर मुद्दा राज्य सरकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर अन्य के अलावा प्रमुख सचिव राहुल तिवारी, अतिरिक्त सचिव कमल कुमार गर्ग, अतिरिक्त निदेशक डॉ. अंजुमन भास्कर और अजयवीर सिंह सराओ तथा जीएम (वित्त) सरवेश कुमार उपस्थित थे।

ईडी के सामने पेश हुए जालंधर सेंट्रल के विधायक रमन अरोड़ा

एजेंसी (हि.स.)
चंडीगढ़

जालंधर सेंट्रल से आम आदमी पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जालंधर कार्यालय में पेश हुए। ईडी के समन पर विधायक निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचे। सफेद कुर्ता-पायजामा पहने रमन अरोड़ा की कार्यालय पहुंचने की वीडियो भी सामने आई है। कार्यालय में प्रवेश से पहले उनका निजी सामान जमा करवाया गया, जिसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए अंदर भेजा गया।

जानकारी के अनुसार यह मामला आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़ा हुआ है। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो पहले ही रमन अरोड़ा को इस मामले में गिरफ्तार कर चुका है। विजिलेंस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की है।

रमन अरोड़ा पर ुकानदारों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कथित तौर पर अवैध वसूली करने के आरोप भी लगे हैं। विजिलेंस ब्यूरो ने उनके खिलाफ 1.10 करोड़ रुपये की संपत्ति से संबंधित मामला दर्ज किया था। गिरफ्तारी के बाद अदालत ने उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ, आय से अधिक संपत्ति और अवैध वसूली के आरोपों की जांच तेज

आरोप है कि रमन अरोड़ा ने सहायक टाउन प्लानर (एटीपी) सुखदेव वशिष्ठ के साथ मिलकर कथित रूप से अवैध नोटिस जारी करवाए। इन नोटिसों के जरिए भवन मालिकों को सीलिंग और तोड़फोड़ की कार्रवाई की धमकी दी जाती थी तथा मामले वापस लेने या निपटाने के बदले धन की मांग की जाती थी।

अधिकारियों के अनुसार ईडी ने विधायक को 2 जून को जालंधर कार्यालय में तलब किया था, जहां पीएमएलए के तहत उनका बयान दर्ज किया जाना था। मामले की जांच जारी है और एजेंसियां वित्तीय लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच कर रही हैं।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने गेहूं खरीद सीजन की सफलता के लिए विभाग की प्रशंसा की

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

धान के आगामी सीजन की तैयारी अभी से शुरू करने के दिए निर्देश

प्रदेश के गरीब वर्ग को पौष्टिक भोजन प्रदान करने से संबंधित पंजाब सरकार की महत्वपूर्ण 'मेरी रसोई योजना' के तहत अब तक 4.50 लाख फूड किटें वितरित की जा चुकी हैं, जो इस योजना की सफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस योजना के तहत प्रदेश के 40 लाख गरीब परिवारों को ऐसी किटें प्रदान की जा रही हैं।

आज यहां एक बैठक के दौरान यह जानकारी देते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री लाल चंद कटारूचक्क ने कहा कि प्रत्येक किट में मासिक खपत के लिए दो किलो दाल, दो किलो चीनी, एक किलो नमक, 200 ग्राम हल्दी पाउडर और एक लीटर सरसों का तेल शामिल है। ये फूड किटें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र लाभार्थियों को पहले से वितरित किए जा रहे गेहूं के अतिरिक्त प्रदान की जा रही हैं।

मंत्री ने आगे कहा कि पात्र लाभार्थियों को प्रतिदिन 50,000 ऐसी फूड किटें वितरित की जा रही हैं। बैठक के दौरान, मंत्री ने संपन्न गेहूं खरीद सीजन की सफलता के लिए विभाग की प्रशंसा भी की और इस शानदार सफलता का श्रेय मंडियों में मजबूत बुनियादी ढांचे को दिया।

मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को गेहूं खरीद सीजन की तरह ही धान के आगामी खरीद सीजन को सफल बनाने के लिए अग्रिम तैयारी शुरू करने को कहा। इस अवसर पर अन्य के अलावा प्रमुख सचिव राहुल तिवारी, अतिरिक्त सचिव कमल कुमार गर्ग, अतिरिक्त निदेशक डॉ. अंजुमन भास्कर और अजयवीर सिंह सराओ, तथा जीएम (वित्त) सरवेश कुमार शामिल थे।

गैंगस्टरों ते वार का 133वां दिनः पंजाब पुलिस द्वारा 499 स्थानों पर छापेमारी; 221 गिरफ्तार

चंडीगढ़। राज्य में चल रहे निर्णायक अभियान ह्यगैंगस्टरों ते वारह्न के 133वें दिन पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिन्हित एवं मैप किए गए 499 ठिकानों पर छापेमारी की। उल्लेखनीय है कि गैंगस्टरों ते वार पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त राज्य बनाने के लिए एक निर्णायक अभियान है, जिसकी शुरूआत 20 जनवरी, 2026 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव द्वारा की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्यभर में विशेष अभियान चला रही हैं। 133वें दिन पुलिस टीमों ने 221 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के साथ-साथ 2 हथियार भी बरामद किए, जिससे अभियान की शुरूआत के बाद कुल गिरफ्तारियों की संख्या 33,340 हो गई है। इसके अतिरिक्त 81 व्यक्तियों के विरुद्ध एहतियाती कार्रवाई की गई, जबकि 10 व्यक्तियों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीमों ने 3 भगोड़े अपराधियों (पीओ) को भी गिरफ्तार किया। लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में गुप्त रूप से जानकारी दे सकते हैं तथा अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों संबंधी सूचनाएं भी साझा कर सकते हैं। इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के विरुद्ध अपनी मुहिम युद्ध नशों विरुद्ध को 458वें दिन भी जारी रखते हुए आज 91 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया तथा उनके कब्जे से 910 ग्राम हेरोइन, 285 नशीली गोलियां और 5.07 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की। इसके साथ ही केवल 458 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 66,282 हो गई है। नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत पंजाब पुलिस ने आज 11 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार करवाने के लिए भी प्रेरित किया।

पुलिस टीमों ने 81 व्यक्तियों के विरुद्ध एहतियाती कार्रवाई की, 10 को पूछताछ के बाद किया रिहा

पंजाब सरकार ने हजारों कर्मचारियों के हित में लिया ऐतिहासिक फैसला : कुलदीप सिंह धालीवाल

सिटी दर्पण संवाददाता
अमृतसर

अजनाला विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि हाल ही में पंजाब मंत्रिमंडल द्वारा राज्य के 65 हजार से अधिक आउटसोर्स, ठेका, दैनिक वेतनभोगी तथा अन्य अस्थायी कर्मचारियों के कल्याण के लिए लिया गया ऐतिहासिक निर्णय उनके सुनहरे भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

पंजाब सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि लंबे समय से ठेकेदारी व्यवस्था के अंतर्गत कार्य कर रहे कर्मचारियों को अब सीधे सरकारी व्यवस्था के अधीन लाने तथा उन्हें नियमित रोजगार की दिशा में अवसर प्रदान करने की यह एक बड़ी पहल है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने हमेशा कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता दी है और यह निर्णय हजारों कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित एवं मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि पंजाब मंत्रिमंडल द्वारा कर्मचारी हितैषी नए कानूनों को मंजूरी मिलने से सरकार और कर्मचारियों के बीच सीधा संबंध स्थापित होगा तथा ठेकेदारों की भूमिका समाप्त हो जाएगी। इससे आउटसोर्स, ठेका, दैनिक वेतनभोगी एवं अन्य अस्थायी कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा, सम्मान तथा भविष्य की सुनिश्चितता प्राप्त होगी।

विधायक धालीवाल ने बताया कि पंजाब के 51 विभागों में कार्यरत 65,048 कर्मचारी इस नीति के दायरे में आएंगे, जबकि पहले चरण में 26 हजार से अधिक कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि बिजली, स्थानीय निकाय, शिक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, कृषि तथा अन्य

महत्वपूर्ण विभागों में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के लिए यह निर्णय नई उम्मीद लेकर आया है।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करने वाले फायर कर्मचारियों, लाइनमैनों, सीवर कर्मचारियों तथा सफाई सेवकों के लिए विशेष प्रावधान करते हुए तीन वर्ष की सेवा के बाद पात्रता प्रदान करने का निर्णय उनके योगदान का सम्मान है और इससे इन वर्गों को बड़ी राहत मिलेगी।

श्री धालीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों के समाधान के लिए पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार जनता से किए गए प्रत्येक वादे को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है और ये फैसले पंजाब में सुशासन, पारदर्शिता तथा कर्मचारी कल्याण के एक नए अध्याय की शुरूआत करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही पिछले चार वर्षों के दौरान 65 हजार से अधिक सरकारी नौकरियां पूरी पारदर्शिता के साथ प्रदान की हैं, जिससे विभिन्न विभागों की कार्यक्षमता और अधिक मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से दशकों पुरानी ठेकेदारी रोजगार प्रणाली को समाप्त करने तथा सरकारी विभागों में 65 हजार से अधिक कर्मचारियों को नियमित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिससे हजारों ठेका एवं आउटसोर्स कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित होगा।

संक्षिप्त-समाचार

ऑस्ट्रेलियाई नागरिक अमृतसर में लापता, बेटी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से मदद की अपील की

चंडीगढ़। पंजाब में लापता हुए ऑस्ट्रेलियाई नागरिक और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक सुनील शर्मा की बेटी ने अपने पिता का पता लगाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मदद की अपील की। ारत की यात्रा पर आए 66 वर्षीय सुनील शर्मा 22 मई को अमृतसर में लापता हो गए। वे वहां एक संपत्ति की बिक्री के सिलसिले में आए थे। शर्मा का मोहाली में भी एक घर है। उनका परिवार वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है। आस्ट्रेलिया से परिजन उनके साथ संपर्क नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि 22 मई से उनका मोबाइल फोन लगातार बंद आ रहा था। यह मामला आस्ट्रेलियाई मीडिया ने भी उठाया है। अमृतसर ग्रामीण पुलिस की जांच के अनुसार, सुनील शर्मा के भाई सनी शर्मा इस मामले में मुख्य संदिग्ध हैं। सनी अपने परिवार के साथ फरार है। एक वीडियो संदेश में सुनील शर्मा की बेटी सुरभि शर्मा ने पंजाब के मुख्यमंत्री से अपने पिता को ढूंढने में मदद करने की अपील की। सुरभि ने कहा, मैं अपने पिता की वापसी के लिए मदद मांग रही हूं। मेरे पिता 22 मई से अमृतसर से लापता हैं। हमें अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनका फोन बंद है। उन्होंने बताया कि उनके पिता ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में गणित के शिक्षक थे। सुरभि ने कहा, मेरे पिता पंजाबी हैं और उन्हें पंजाब से बहुत प्यार है। उन्हें पंजाब से इतना प्यार था कि उन्होंने वहां संपत्ति खरीदने के लिए निवेश किया। सुरभि ने मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्य सरकार से अनुरोध किया कि वे अपने संसाधनों का उपयोग कर उन्हें ढूंढने में मदद करें। उन्होंने कहा कि उनके पिता अमृतसर में संपत्ति पर पुताई का काम करवाने गए थे। अमृतसर पुलिस ने इस मामले में अपहरण का मामला दर्ज किया है। कांबो थाना प्रभारी शमशेर सिंह ने बताया, सनी अपने परिवार के साथ फरार है। हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। अधिकारी ने बताया कि सनी हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम और आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में भी फरार है।

बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने हासिल किया 152 एमएम तोप के गोलों का बड़ा ऑर्डर

चंडीगढ़। प्रिसिजन इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की अग्रणी कंपनी, बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने लार्ज-कैलिबर एम्युनिशन सेगमेंट में बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने की घोषणा की है। कंपनी ने भारत की एक प्रमुख विस्फोटक और गोला-बारूद बनाने वाली (एनर्जेटिक्स) कंपनी को 152 एमएम तोप के गोलों (आर्टिलरी शेल्स) की 30,000 यूनिट्स सप्लाई करने का शुरूआती अनुबंध हासिल किया है। यह साझेदारी घरेलू रक्षा क्षेत्र में बालू फोर्ज के विस्तार की दिशा में एक अहम मील का पत्थर है। इस अहम ऑर्डर की आपूर्ति (सप्लाई) जून 2026 से शुरू होने वाली है। इस ऑर्डर को पूरा करने का काम कर्नाटक के बेलगाम में बीएफआईएल की नई फैसिलिटी से होगा। यह फैसिलिटी 100 प्रतिशत स्वदेशी तरीके से बनी है और यहां पूरी तरह ऑटोमेटेड एम्प्टी शेल प्रोडक्शन लाइन लगी है।

मीशो ने बीएसई के साथ साझेदारी में प्रोजेक्ट शिखर शुरू किया

चंडीगढ़। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मीशो ने बीएसई के साथ साझेदारी में प्रोजेक्ट शिखर शुरू किया है। इसका उद्देश्य एमएसएमई को बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक सूचीबद्ध संस्था बनने में मदद करना है, ताकि वो अपने विकास के लिए पूंजी प्राप्त कर सकें। इस साझेदारी को औपचारिक रूप देने के लिए मिस लोपामुद्रा राव, वाइस प्रेसिडेंट एवं जनरल काउंसिल, मीशो और श्री सुंदरम राममूर्ति, एमडी एवं सीईओ, बीएसई की मौजूदगी में एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। यह जमीनी स्तर पर काम करने वाले डिजिटल व्यवसायों को संस्थागत पूंजी प्राप्त करने में समर्थ बनाने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। लोपामुद्रा राव, वाईस प्रेसिडेंट एवं जनरल काउंसेल, मीशो ने कहा कि हमारे सेलर ईकोसिस्टम का एक बड़ा हिस्सा उन उद्यमी व्यवसायों का है, जो हमारे प्लेटफॉर्म पर बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। एक सफल ई-कॉमर्स ब्रांड से निवेश के लिए तैयार संस्था बनना कठिन होता है। लेकिन प्रोजेक्ट शिखर ने इस बाधा को दूर कर दिया है।

जेईई एडवांस्ड के टॉपर छात्रों को सम्मानित किया

चंडीगढ़। चंडीगढ़ के जेईई एडवांस्ड 2026 में क्वालीफाई हुए 35 छात्रों को मंगलवार को आकाश एजुकेशन, चंडीगढ़ सेंटर में सम्मानित किया गया। आकाश सेंटर के शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में, ईशान गोयल ने 272 अंकों के साथ एआईआर 113 हासिल की । सार्थक गौतम ने 210 अंकों के साथ एआईआर 992, आरव सिंह एआईआर 2448 और 179 अंक, भरत मलिक एआईआर 2512 और 178 अंक और अर्शप्रीत सिंह ने एआईआर 2533 और 178 अंक प्राप्त किये । अन्य उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वालों में अमितोज तुर्का एआईआर 3293, महित सिंगला एआईआर 4164, अजय प्रताप सिंह एआईआर 4500, अनमोल वर्मा एआईआर 4708 और समर सिंगला एआईआर 5243 शामिल हैं। छात्रों के अनुसार, उन्हें अपनी तैयारी के दौरान निरंतर मार्गदर्शन, शैक्षणिक सहायता और मेंटरशिप प्राप्त हुई। छात्रों ने कहा, अध्ययन सामग्री, कक्षा सत्र, मॉक टेस्ट और नियमित मूल्यांकन ने हमें अपनी अवधारणाओं को मजबूत करने और अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद की।उन्होंने आगे कहा, शिक्षकों और अभिभावकों के सहयोग के बिना यह उपलब्धि संभव नहीं थी। छात्रों की इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर उन्हें बधाई देते हुए, डिप्टी रीजनल डायरेक्टर -आकाश एजुकेशनल, जसदीप सिंह बाबरा ने कहा, जेईई एडवांस्ड 2026 में अपने छात्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर हमें बेहद गर्व है। उनकी सफलता अटूट समर्पण, अनुशासित तैयारी और उत्कृष्टता प्राप्त करने की प्रबल इच्छा का परिणाम है।

प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पुतले फूंके

नीट पेपर लीक और सीबीएसई की खराब कार्यप्रणाली के खिलाफ कांग्रेस का राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन, सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध मार्च और धरने आयोजित किए गए

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब भर में कांग्रेस कार्यकताओं ने आज नीट के प्रश्नपत्रों के बार-बार लीक होने और सीबीएसई में व्याप्त गंभीर अव्यवस्थाओं के खिलाफ विरोध मार्च और धरने दिए गए।

इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पुतले भी फूंके तथा बार-बार की विफलताओं के लिए प्रधान को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकताओं के साथ बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और युवाओं ने भी राज्य के विभिन्न हिस्सों, जिनमें लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पटियाला, बठिंडा तथा अन्य शहर और कस्बे शामिल थे, में आयोजित इन विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया।

चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि देशभर के लगभग 22 लाख विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा दी थी, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक हो गया था। उन्होंने कहा कि यह दूसरी बार है, जब नीट का पेपर लीक हुआ है और इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि जरा उन विद्यार्थियों की स्थिति की कल्पना कीजिए, जिन्होंने वर्षों तक कड़ी मेहनत की हो और बाद में पता चले कि प्रश्नपत्र लीक हो गया था, परीक्षा रद्द कर दी गई है और अब उन्हें दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी।

वड़िंग ने विद्यार्थियों के प्रति प्रधानमंत्री की उदासीनता और असंवेदनशील रवैये की आलोचना करते हुए, सवाल किया कि वह धर्मेंद्र प्रधान जैसे अयोग्य और अक्षम मंत्री को क्यों बचा रहे हैं।

वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने मांग की कि बार-बार नीट परीक्षा आयोजित करने में विफल रही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को भंग किया जाए और नीट जैसी परीक्षाओं के लिए पूरी तरह विश्वसनीय एवं पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए, क्योंकि इससे देश के लाखों विद्यार्थियों के भविष्य का प्रश्न जुड़ा हुआ है। उन्होंने सीबीएसई की ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली में पाई गई गंभीर खामियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली दोषपूर्ण और अविश्वसनीय साबित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसका कारण यह है कि जिस कंपनी कोएमप्ट एडुटेक को यह ठेका दिया गया है, उसके पास इस प्रकार की परीक्षाओं के संचालन का आवश्यक अनुभव और विशेषज्ञता नहीं है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि कोएमप्ट एडुटेक को विशेष रियायतें दी गईं और नियमों में बदलाव करके उसे लाभ पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि इस कंपनी को पहले तेलंगाना सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट किया जा चुका था, फिर भी सीबीएसई ने उसे ठेका दे दिया, जिसके कारणों की जानकारी वही बेहतर दे सकती है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कोएमप्ट एडुटेक को यह विशेष छूट क्यों दी गई, जबकि यह कंपनी विद्यार्थियों के जीवन और करियर के साथ खिलवाड़ कर रही है।

नेपाल अमेरिका का महत्वपूर्ण और मजबूत साझेदार : अमेरिकी मंत्री सारा रोजर्स

आर्थिक सहयोग और तकनीकी निवेश पर जोर, एमसीसी परियोजना को बताया महत्वपूर्ण

एजेंसी (हि.स.)

काठमांडू

अमेरिकी विदेश मंत्रालय में सार्वजनिक कूटनीति संबंधी उप विदेशमंत्री सारा बी. रोजर्स ने कहा है कि अमेरिका नेपाल को एक महत्वपूर्ण और मजबूत साझेदार के रूप में देखता है। उन्होंने नेपाल के प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास, एमसीसी परियोजना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भू-राजनीतिक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण स्पष्ट किया।

तीन दिवसीय नेपाल यात्रा के समापन से पहले काठमांडू में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में रोजर्स ने कहा कि नेपाल के विदेशमंत्री शिशिर खनाल और सूचना एवं संचार मंत्री विक्रम तिमिल्सिना के साथ उनकी बैठकें बेहद उपयोगी रहीं। उन्होंने कहा कि अमेरिका नेपाल के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने, कारोबारी माहौल में सुधार लाने और डिजिटल पहुंच का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। रोजर्स ने नेपाल में नवाचार और आर्थिक विकास की व्यापक संभावनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि देश का प्रौद्योगिकी क्षेत्र 'सिलिकॉन वैली' जैसी क्षमता रखता है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डेटा सेंटरों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल कारोबारी वातावरण विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

फोटोः हि.स.

स्टारलिंक इंटरनेट सेवा के संभावित प्रवेश पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अमेरिका नेपाल की संप्रभुता और उसकी आंतरिक प्रक्रियाओं का सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कंपनियां नेपाल में कब और कैसे निवेश करेंगी, यह नेपाल और संबंधित कंपनियों का विषय है, लेकिन अमेरिका नेपाल में इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार देखना चाहता है।

रोजर्स ने 55 करोड़ डॉलर की मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन (एमसीसी) परियोजना को नेपाल की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा क्षेत्र के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण निवेश बताया। उन्होंने विश्वास जताया कि नेपाल सरकार इस परियोजना को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि एमसीसी केवल अमेरिकी सहायता कार्यक्रम नहीं, बल्कि वास्तविक साझेदारी का उदाहरण है, क्योंकि इसमें नेपाल भी लगभग 19 करोड़ 70 लाख डॉलर का निवेश कर रहा है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन

रोजर्स ने कहा कि अब यूएसएआईडी स्वतंत्र एजेंसी के रूप में कार्य नहीं कर रही है और इसकी गतिविधियां अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधीन नए विदेशी सहायता कार्यालय के माध्यम से संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब केवल सहायता देने की बजाय व्यापार और साझेदारी आधारित संबंधों को प्राथमिकता दे रहा है। इंटरनेट सेंसरशिप पर उन्होंने कहा कि सरकारों को यह तय नहीं करना चाहिए कि नागरिक क्या सोचें या क्या देखें। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि धोखाधड़ी या बाल यौन शोषण जैसे अपराधों पर कार्रवाई न हो। रोजर्स ने कहा कि गलत सूचना और डीपफेक जैसी चुनौतियों से निपटने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रभावी भूमिका निभा सकता है।

भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर अमेरिका का रुख

नेपाल में अमेरिका, चीन और भारत के बीच बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को लेकर पूछे गए सवाल पर रोजर्स ने कहा कि अमेरिका का ध्यान केवल नेपाल-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि अमेरिका नेपाल के साथ आर्थिक, तकनीकी और लोकतांत्रिक सहयोग बढ़ाने में रुचि रखता है तथा किसी भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बनने का उद्देश्य नहीं है।

नेपाल-भारत संबंधों को विकास आधारित नई दिशा देने का समय : रवि लामिछाने

एजेंसी (हि.स.)

काठमांडू

राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (रास्वपा) के अध्यक्ष रवि लामिछाने ने कहा है कि नेपाल और भारत के बीच संबंधों को अतीत की बहसों से आगे बढ़ाकर विकास, आर्थिक सहयोग और साझा समृद्धि के आधार पर नए सिरे से परिभाषित करने का समय आ गया है। भारत की औपचारिक यात्रा शुरू करने से पहले जारी संदेश में उन्होंने कहा कि नेपाल में उभर रहे राजनीतिक परिवर्तन और भारत की तेज आर्थिक प्रगति दोनों देशों के लिए नए अवसर लेकर आए हैं। लामिछाने ने कहा कि नेपाल में हुए राजनीतिक बदलाव किसी हिंसा, सैन्य तख्तापलट, विदेशी हस्तक्षेप या संवैधानिक संकट का परिणाम नहीं हैं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से आए परिवर्तन का उदाहरण हैं। उन्होंने इसे 'मतपेटी क्रांति' बताते हुए कहा कि नेपाल ने यह साबित किया है कि लोकतंत्र आज भी परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम है। उनके अनुसार देश सुशासन, विकास और जनता के प्रति प्रत्यक्ष जवाबदेही के सिद्धांतों पर आगे बढ़ रहा है। लामिछाने ने कहा कि रास्वपा नेपाल की नई राजनीतिक वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करती है। पार्टी ने युवाओं को परिणाम आधारित राजनीति से जोड़ते हुए पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अतीत के राजनीतिक बोझ और पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर विदेश नीति को नए दृष्टिकोण से देखती है। उनका कहना है कि नेपाल और भारत केवल पड़ोसी देश नहीं, बल्कि एक प्राचीन और गौरवशाली सभ्यता के साझेदार हैं। जनकपुर और अयोध्या, पशुपतिनाथ और केदारनाथ, तथा लुम्बिनी और बोधगया जैसे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध दोनों देशों की साझी विरासत को मजबूत बनाते हैं। लामिछाने ने कहा

फोटोः हि.स.

कि दोनों देशों को यह देखने के बजाय कि अतीत में क्या हासिल हुआ, इस पर ध्यान देना चाहिए कि भविष्य में क्या हासिल किया जा सकता है। उन्होंने नेपाल के आर्थिक रूपांतरण को अपनी राजनीतिक सोच का प्रमुख लक्ष्य बताया। रास्वपा अध्यक्ष ने भारत की आर्थिक प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि नेपाल इस विकास यात्रा का सहभागी बनना चाहता है। उन्होंने प्रस्तावित रक्सौल-काठमांडू रेलमार्ग को परिवर्तनकारी परियोजना बताते हुए कहा कि इसके पूरा होने से व्यापार, पर्यटन, परिवहन और क्षेत्रीय संपर्क में व्यापक बदलाव आएगा। उन्होंने पोखरा और लुम्बिनी से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए सीधी उड़ानों की संभावना, काठमांडू-बेंगलुरु डिजिटल कॉरिडोर तथा नेपाल में रासायनिक उर्वरक उद्योग की स्थापना जैसे विषयों का भी उल्लेख किया। उन्होंने नेपाल में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसे संस्थानों की स्थापना का स्वागत करने की बात कही।

बांग्लादेश में तालाब के घाट से बच्ची को खींच ले गया मगरमच्छ

फोटोः हि.स.

एजेंसी (हि.स.)

ढाका

बांग्लादेश के बागेरहाट स्थित ऐतिहासिक खानजहान अली दरगाह के तालाब में सोमवार रात एक सात वर्षीय बच्ची को मगरमच्छ खींचकर ले गया। घटना के बाद दमकल कर्मियों और स्थानीय लोगों ने संयुक्त रूप से तलाश अभियान शुरू किया, लेकिन देर रात तक बच्ची का पता नहीं चल सका।

रिपोर्ट के अनुसार बच्ची फातिमा अपनी मां के साथ दरगाह परिसर में रहती थी। वह महिला घाट पर नहाने गई थी, तभी तालाब में मौजूद मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मगरमच्छ बच्ची को पानी की गहराई में ले गया। फायर सर्विस अधिकारियों ने बताया कि मगरमच्छ के कारण बचाव अभियान जोखिम भरा है, फिर भी खोजबीन जारी है। उल्लेखनीय है कि इसी तालाब में अप्रैल में एक कुत्ते पर मगरमच्छ के हमले का वीडियो भी वायरल हुआ था।

फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में वीरगंज के मेयर गिरफ्तार

काठमांडू। नेपाल की आर्थिक राजधानी वीरगंज के मेयर राजेशमान सिंह को पुलिस ने मंगलवार सुबह पर्सा जिले के ठोरी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। उन्हें एक रिसॉर्ट से दबोचा गया। उन्हें किसी अन्य व्यक्ति की बेटी को अपनी बताकर उसका जन्म प्रमाणपत्र बनवाने और इसी आधार पर उसके नागरिकता दिलाने और उसका पासपोर्ट बनवाकर उसे विदेश भेजने का आरोप है। जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा प्रमुख सुदीपराज पाठक ने यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी पाठक ने बताया कि मेयर सिंह को जिला अदालत पर्सा द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के आठ दिन बाद गिरफ्तार करने में सफलता मिली। इस संबंध में मेयर सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मेयर सिंह गिरफ्तारी की अनुमति मिलने के बाद एक दिन अदालत में उपस्थित हुए, लेकिन बाद में फरार हो गए थे। नेपाल में इस अपराध में दोष सिद्ध होने पर 7 वर्ष तक की कैद और 70 हजार नेपाली रुपये तक के जुमार्ने का प्रावधान है।

कर्नाटक की नई कैबिनेट पर मंथन के लिए दिल्ली में डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया

फोटोः हि.स.

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

कर्नाटक में नई सरकार के गठन और मंत्रिमंडल को अंतिम रूप देने के लिए डीके शिवकुमार और कार्यवाहक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया दिल्ली में है। दोनों नेताओं की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक होनी है, जिसमें मंत्रिमंडल गठन और प्रमुख संगठनात्मक नियुक्तियों पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली में सिद्धारमैया की होटल से निकलते हुए विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से भी मुलाकात हुई। इस दौरान जब पत्रकारों ने उनसे मल्लिकार्जुन खरगे के साथ होने वाली बैठक के एजेंडे के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में होने वाली चर्चा के लिए डीके शिवकुमार ने मंत्रिमंडल के संभावित सदस्यों की एक प्रारंभिक सूची तैयार कर ली है। कांग्रेस नेतृत्व के साथ विचार-विमर्श के बाद इस सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि पहले चरण में 10 से 20 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। बताया जा रहा है कर्नाटक में नई सरकार गठन के लिए अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और अंतिम मंजूरी के बाद नामों की घोषणा की जाएगी।

गुवाहाटी में सनसनी, एक ही विद्यालय की चार छात्राएं लापता

गुवाहाटी। गुवाहाटी के बशिष्ठ क्षेत्र में एक ही विद्यालय की चार छात्राओं के रहस्यमय ढंग से लापता होने की घटना से सनसनी फैल गई है। छात्राओं के परिजन और स्थानीय लोग गहरी चिंता में हैं। लापता छात्राओं की पहचान दैमारी, बरुवा, सिंह और राय उपाधिधारी के रूप में हुई है। चारों छात्राएं बेलतला माझीपारा मिडिल इंग्लिश स्कूल की छात्राएं हैं तथा बशिष्ठ के बेहारबाड़ी क्षेत्र की निवासी हैं। परिजनों के अनुसार, छात्राएं सोमवार सुबह विद्यालय जाने के लिए घर से निकली थीं, लेकिन उसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल सका। काफी खोजबीन के बावजूद छात्राओं का कोई सुराग नहीं मिला है। घटना के बाद परिजनों में चिंता का माहौल है। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है और छात्राओं की तलाश के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। पुलिस विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच कर रही है तथा छात्राओं के बारे में जानकारी जुटाने में लगी हुई है।

मणिपुर में दो उग्रवादी और दो मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार

एजेंसी (हि.स.)

इंफाल

मणिपुर में सुरक्षा बलों ने सोमवार को अलग-अलग अभियानों में चार लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन आरपीएफ/पीएलए के दो सक्रिय कैडर तथा मादक पदार्थ तस्करी के दो आरोपित शामिल हैं।

मंगलवार को राज्य पुलिस मुख्यालय द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, सुरक्षा बलों ने इंफाल पूर्व जिले में चलाए गए अभियान के दौरान आरपीएफ/पीएलए के दो सक्रिय कैडरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान खुरई निंगथौबुंग लैकाई निवासी मैबाम अरुण सिंह उर्फ उरु (49) तथा पौराबी आवांग लैकाई निवासी थांगजाम सुरंकुमार सिंह उर्फ अचौबा उर्फ राजेश (30) के रूप में हुई है। अरुण सिंह को पोरोमपट थाना क्षेत्र के टॉप आवांग लैकाई स्थित सामुदायिक भवन के निकट से जबकि

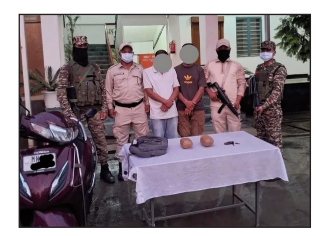

सुरंकुमार सिंह को टॉप माखा लैकाई से गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक जांच में दोनों के उगाही और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त होने की जानकारी सामने आई है। सुरक्षा एजेंसियां उनके नेटवर्क और गतिविधियों की विस्तृत जांच कर रही हैं। एक अन्य अभियान में सुरक्षा बलों ने कोइरेंगी स्थित सीएमसी अस्पताल के निकट दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में संदिग्ध ब्राउन शुगर बरामद की। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान कांगलाटोंगबी हाटिक खुवा निवासी पूर्ण बहादुर कार्के (40) और कांगलाटोंगबी शांतिपुर निवासी लविंग्सन (37) के रूप में हुई है।

विविध दर्पण

विश्व साइकिल दिवसः स्वस्थ जीवन, स्वच्छ पर्यावरण और सतत् विकास की मजबूत सवारी

हर वर्ष 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस केवल एक साधारण परिवहन साधन के रूप में साइकिल की उपयोगिता को याद करने का अवसर नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा बचत और सतत विकास में इसके महत्वपूर्ण योगदान को भी रेखांकित करता है। आधुनिक समय में जब दुनिया प्रदूषण, यातायात जाम, बढ़ती ईंधन खपत और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, तब साइकिल एक सरल, सुलभ और प्रभावी समाधान के रूप में सामने आती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2018 में 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मान्यता प्रदान की थी। इसके पीछे उद्देश्य साइकिल को एक ऐसे साधन के रूप में बढ़ावा देना था जो किफायती होने के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल भी है। संयुक्त राष्ट्र ने माना कि साइकिल सामाजिक समावेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक अवसरों तक पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दुनिया के अनेक देशों में साइकिल केवल मनोरंजन या व्यायाम का साधन नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों से लेकर कामकाजी लोगों और छोटे व्यापारियों तक, बड़ी संख्या में लोग आज भी अपने आवागमन के लिए साइकिल पर निर्भर हैं। विशेष रूप से विकासशील देशों में यह कम लागत वाला और भरोसेमंद परिवहन साधन माना जाता है। भारत में भी साइकिल का एक लंबा सामाजिक और आर्थिक इतिहास रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय तक यह प्रमुख परिवहन साधन रही है। हालांकि मोटर वाहनों के बढ़ते उपयोग के कारण शहरी क्षेत्रों में इसका प्रयोग कुछ कम हुआ, लेकिन हाल के वर्षों में स्वास्थ्य जागरूकता और पर्यावरणीय चिंताओं के चलते साइकिल के प्रति लोगों का रुझान फिर बढ़ा है। कई शहरों में साइकिल ट्रैक विकसित करने और सार्वजनिक साइकिल साझा प्रणाली को बढ़ावा देने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार नियमित साइकिल चलाने से हृदय संबंधी रोगों का खतरा कम होता है, शरीर की सहनशक्ति बढ़ती है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। यह एक ऐसा व्यायाम है जो शरीर के कई अंगों को सक्रिय रखता है तथा मोटापा, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं को नियंत्रित करने में सहायक माना जाता है। इसके साथ ही साइकिल चलाने से तनाव कम करने और मानसिक ताजगी बनाए रखने में भी मदद मिलती है। पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से भी साइकिल का महत्व अत्यंत व्यापक है। यह किसी प्रकार का ईंधन नहीं जलाती और न ही कार्बन उत्सर्जन करती है। ऐसे समय में जब जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है, साइकिल का अधिक उपयोग प्रदूषण कम करने की दिशा में प्रभावी कदम साबित हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि छोटी दूरी की यात्राओं के लिए अधिक लोग साइकिल का उपयोग करें तो शहरों में प्रदूषण और यातायात दबाव दोनों को कम किया जा सकता है। विश्व साइकिल दिवस का एक महत्वपूर्ण संदेश सड़क सुरक्षा से भी जुड़ा है। अनेक देशों में साइकिल चालकों के लिए सुरक्षित मार्ग, बेहतर यातायात व्यवस्था और जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। सड़क पर सभी यातायात उपयोगकर्ताओं के बीच सम्मान और सुरक्षा की भावना विकसित करना इस दिवस के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। भारत सहित दुनिया के कई देशों में इस अवसर पर साइकिल रैलियां, जागरूकता कार्यक्रम, स्वास्थ्य अभियान और सामुदायिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। स्कूलों, कॉलेजों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय प्रशासन की ओर से लोगों को साइकिल अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि साइकिल केवल परिवहन का साधन नहीं, बल्कि स्वस्थ और टिकाऊ जीवनशैली का प्रतीक भी है।

विश्व साइकिल दिवस की शुरुआत

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रैल 2018 में एक प्रस्ताव पारित कर 3 जून को विश्व साइकिल दिवस घोषित किया था। इस पहल का उद्देश्य साइकिल के बहुआयामी लाभों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना और इसके उपयोग को प्रोत्साहित करना था।

स्वास्थ्य के लिए क्यों लाभकारी

विशेषज्ञों के अनुसार नियमित साइकिल चलाने से हृदय स्वास्थ्य बेहतर होता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और शरीर की कार्यक्षमता बढ़ती है। यह कम लागत वाला ऐसा व्यायाम है जिसे लगभग सभी आयु वर्ग के लोग अपनी क्षमता के अनुसार अपना सकते हैं।

पर्यावरण संरक्षण में भूमिका

साइकिल शून्य उत्सर्जन वाला परिवहन साधन है। इसके उपयोग से वायु प्रदूषण कम होता है, ईंधन की बचत होती है और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में मदद मिलती है। सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है।

भारत में बढ़ती जागरूकता

देश के कई शहरों में साइकिल लेन, सार्वजनिक साइकिल प्रणाली और फिटनेस अभियानों के माध्यम से लोगों को साइकिल उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। युवाओं और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नागरिकों के बीच इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। विश्व साइकिल दिवस हमें यह याद दिलाता है कि तकनीकी प्रगति और आधुनिक परिवहन साधनों के दौर में भी साइकिल की उपयोगिता कम नहीं हुई है। यह स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक समानता से जुड़ा ऐसा साधन है जो कम संसाधनों में अधिक लाभ प्रदान करता है। बदलती वैश्विक परिस्थितियों में साइकिल को अपनाना केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य का विषय नहीं, बल्कि स्वच्छ, सुरक्षित और टिकाऊ भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। 3 जून का यह दिवस दुनिया भर के लोगों को इसी संदेश के साथ साइकिल के महत्व को समझने और उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है।

विश्व क्लबफुट दिवसः समय पर उपचार से सामान्य जीवन संभव

हर वर्ष 3 जून को विश्व क्लबफुट दिवस मनाया जाता है। यह दिवस क्लबफुट या जन्मजात टेढ़े पैर (कंजेनिटल टैलिपीस इक्विनोवेरस) जैसी स्थिति के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने, समय पर पहचान और प्रभावी उपचार के महत्व को रेखांकित करने के लिए समर्पित है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यदि क्लबफुट का उपचार जन्म के तुरंत बाद शुरू कर दिया जाए तो अधिकांश बच्चे सामान्य रूप से चल-फिर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। क्लबफुट एक जन्मजात विकृति है, जिसमें बच्चे का एक या दोनों पैर अंदर और नीचे की ओर मुड़े हुए होते हैं। यह समस्या जन्म के समय ही दिखाई देती है और दुनिया भर में लाखों बच्चों को प्रभावित करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विभिन्न चिकित्सा संस्थानों के अनुसार यह जन्मजात अस्थि एवं मांसपेशी संबंधी सबसे सामान्य विकृतियों में से एक है। हालांकि इसके कारणों को लेकर अभी भी शोध जारी है, लेकिन विशेषज्ञ आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों को इसके संभावित कारणों में शामिल मानते हैं। विश्व क्लबफुट दिवस का आयोजन प्रसिद्ध स्पेनिश चिकित्सक डॉ. इग्नासियो पोंसेटी की स्मृति में किया जाता है, जिनका जन्म 3 जून 1914 को हुआ था। उन्होंने क्लबफुट के उपचार के लिए पोंसेटी पद्धति विकसित की थी, जिसे आज दुनिया भर में सबसे प्रभावी और कम खचीर्ली उपचार विधियों में गिना जाता है। इस पद्धति के माध्यम से बिना बड़ी सर्जरी के अधिकांश बच्चों के पैरों को सामान्य स्थिति में लाया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार क्लबफुट का उपचार जितनी जल्दी शुरू किया जाए, उसके परिणाम उतने ही बेहतर होते हैं। आमतौर पर जन्म के कुछ सप्ताह के भीतर उपचार प्रारंभ करने की सलाह दी जाती है। पोंसेटी पद्धति में क्रमिक प्लास्टर, आवश्यक होने पर छोटी शल्य प्रक्रिया और विशेष जूतों या ब्रेस के उपयोग के माध्यम से पैर की स्थिति को धीरे-धीरे सुधारा जाता है। भारत में भी हर वर्ष बड़ी संख्या में बच्चे क्लबफुट के साथ जन्म लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय, विभिन्न राज्य सरकारों, चिकित्सा संस्थानों और सामाजिक संगठनों द्वारा इस विकृति के बारे में जागरूकता फैलाने और निःशुल्क या कम लागत पर उपचार उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। कई सरकारी अस्पतालों और विशेष चिकित्सा केंद्रों में क्लबफुट उपचार सेवाएं उपलब्ध हैं, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भी सहायता मिल रही है। चिकित्सकों का कहना है कि जागरूकता की कमी, सामाजिक संकोच और उपचार में देरी कई बार बच्चों के भविष्य को प्रभावित कर सकती है। यदि समय पर उपचार न मिले तो चलने-फिरने में कठिनाई, शारीरिक अक्षमता और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अभिभावकों को जन्म के बाद बच्चे के पैरों की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए और किसी भी असामान्यता की स्थिति में विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। विश्व क्लबफुट दिवस के अवसर पर दुनिया भर में जागरूकता अभियान, स्वास्थ्य शिविर, चिकित्सा परामर्श कार्यक्रम और जनसंपर्क गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य यह संदेश देना है कि क्लबफुट कोई लाइलाज बीमारी नहीं है और सही समय पर उपचार मिलने पर बच्चे सामान्य जीवन जी सकते हैं।

क्या है क्लबफुट

क्लबफुट एक जन्मजात स्थिति है, जिसमें शिशु का पैर अंदर और नीचे की ओर मुड़ा हुआ होता है। यह समस्या एक या दोनों पैरों में हो सकती है और जन्म के समय ही इसकी पहचान की जा सकती है।

पोंसेटी पद्धति की सफलता

डॉ. इग्नासियो पोंसेटी द्वारा विकसित उपचार पद्धति को विश्वभर में क्लबफुट के उपचार का मानक माना जाता है। समय पर अपनाए जाने पर इससे अधिकांश मामलों में सफल परिणाम प्राप्त होते हैं।

भारत में उपचार सुविधाएं

देश के अनेक सरकारी और निजी अस्पतालों में क्लबफुट के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। कई राज्यों में विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को निःशुल्क उपचार और आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण संदेश

विशेषज्ञों के अनुसार जन्म के तुरंत बाद क्लबफुट की पहचान और उपचार शुरू करना सबसे महत्वपूर्ण है। उपचार में देरी होने पर जटिलताएं बढ़ सकती हैं, जबकि समय पर देखभाल से बच्चा सामान्य रूप से चल-फिर सकता है। विश्व क्लबफुट दिवस समाज को यह संदेश देता है कि जन्मजात विकृतियों के प्रति जागरूकता, समय पर चिकित्सा सहायता और उचित उपचार से बच्चों का भविष्य बेहतर बनाया जा सकता है। यह दिवस स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और प्रत्येक बच्चे को स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन का अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में वैश्विक प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है।

नॉर्वे शतरंज: प्रज्ञानंद ने अलीरेजा फिरोजा को क्लासिकल मुकाबले में हराया

महिला वर्ग: बिबिसारा असाउबायेवा की बढ़त मजबूत, दिव्या देशमुख दूसरे स्थान पर

एजेंसी (हि.स.)
ओस्लो (नॉर्वे)

नॉर्वे शतरंज 2026 के सातवें दौर में रोमांच चरम पर रहा। इस दौर में एक मुकाबले का फैसला क्लासिकल शतरंज में हुआ, जबकि दो अन्य मुकाबलों का नतीजा आमार्गेडन टाईब्रेकर से निकला। सोमवार को खेले गए सातवें दौर में दिन का सबसे बड़ा उलटफेर भारत के युवा ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानानंद ने किया।

उन्होंने क्लासिकल मुकाबले में अलीरजा फिरोजजा को पराजित कर खिताबी दौड़ को और रोमांचक बना दिया। लंबे समय तक चले संघर्षपूर्ण मुकाबले में प्रज्ञानानंद ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए अपनी बढ़त को जीत में बदल दिया। टूर्नामेंट में यह अलीरजा फिरोजजा की दूसरी क्लासिकल हार रही। दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन और विन्सेंट कीमर के बीच क्लासिकल मुकाबला ड्रॉ रहा। इसके बाद हुए आमार्गेडन मुकाबले में कार्लसन ने बाजी मारते हुए अतिरिक्त अंक हासिल किए और शीर्ष खिलाड़ियों पर दबाव बनाए रखा।

वेस्ली सो शीर्ष पर बरकरार

वहीं मौजूदा विश्व चैंपियन डी. गुकेश और वेस्ली सो के बीच क्लासिकल मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ। आमार्गेडन में गुकेश ने जीत दर्ज कर महत्वपूर्ण अतिरिक्त अंक अपने नाम किए। सातवें दौर के बाद वेस्ली सो 12.5 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर बने हुए हैं। अलीरजा फिरोजजा 10 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि मैग्नस कार्लसन, विन्सेंट कीमर और आर. प्रज्ञानानंद 9-9 अंकों के साथ खिताब की दौड़ में बने हुए हैं। महिला वर्ग में बिबिसारा असाउबायेवा की बढ़त मजबूत, दिव्या देशमुख दूसरे स्थान पर नॉर्वे शतरंज महिला प्रतियोगिता में बिबिसारा असाउबायेवा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी बढ़त और मजबूत कर ली। सफेद मोहरों से खेलते हुए उन्होंने झू जिनर को क्लासिकल मुकाबले में हराकर पूरे तीन अंक हासिल किए। मध्य खेल में बढ़त बनाने के बाद उन्होंने आत्मविश्वास के साथ जीत सुनिश्चित की। भारत की दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी के बीच क्लासिकल मुकाबला ड्रॉ रहा। हालांकि आमार्गेडन मुकाबले में दिव्या ने काले मोहरों से खेलते हुए जीत दर्ज की और अतिरिक्त अंक हासिल किए। दूसरे मुकाबले में मौजूदा महिला विश्व चैंपियन जू वेनजुन और अन्ना मुजीचुक के बीच क्लासिकल बाजी बराबरी पर समाप्त हुई।

फोटो: हि.स.

इसके बाद आमार्गेडन में मुजीचुक ने जीत हासिल कर महत्वपूर्ण अतिरिक्त अंक अपने खाते में जोड़े। सातवें दौर के बाद बिबिसारा असाउबायेवा 12.5 अंकों के साथ पहले स्थान पर हैं, जबकि दिव्या देशमुख 10 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर बनी हुई हैं। अन्ना मुजीचुक 9.5 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं।

सर्राफा बाजार में लगातार दूसरे दिन सस्ता हुआ सोना, चांदी की कीमत में कोई बदलाव नहीं

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली,

घरेलू सर्राफा बाजार में सोने की कीमत में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन शुरूआती कारोबार के दौरान गिरावट का रुख बना हुआ है। सोने की कीमत में आई गिरावट के कारण चेन्नई के अलावा देश के ज्यादातर हिस्सों में मंगलवार को ये चमकीली धातु 750 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 820 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ती हो गई। वहीं चेन्नई में सोने की कीमत में मंगलवार को 1,300 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,420 रुपये प्रति 10 ग्राम तक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सोना के विपरीत चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

भाव में आई कमी के कारण देश के सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना मंगलवार को 1,56,210 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,58,170 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं 22 कैरेट सोना मंगलवार को 1,43,190 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,44,990 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। वहीं चांदी के भाव में बदलाव नहीं होने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में मंगलवार को भी 2,79,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। दिल्ली

फोटो: हि.स.

में मंगलवार को 24 कैरेट सोना 1,56,360 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,43,340 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,56,210 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,43,190 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,56,260 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,43,240 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना मंगलवार को 1,58,170 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,44,990 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,56,210 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,43,190 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,56,260 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,43,240 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,56,360 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,43,340 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,56,260 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,43,240 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना मंगलवार को 1,56,360 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 1,43,340 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी मंगलवार को सोने के भाव में गिरावट का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। इन तीनों राज्यों की राजधानियों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना 1,56,210 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह इन तीनों शहरों के सर्राफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 1,43,190 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

स्टॉक मार्केट में फ्लैट एंट्री के बाद याश्वी ज्वेलर्स के शेयरों में आई तेजी

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

यशस्वी ब्रांड नेम से गोल्ड ज्वेलरी सेक्टर के लिए काम करने वाली कंपनी याश्वी ज्वेलर्स के शेयरों ने मंगलवार को स्टॉक मार्केट में फ्लैट एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को निराश कर दिया। हालांकि बाद में शेयरों में शुरू हुई खरीदारी से आईपीओ निवेशकों के चेहरे खिल गए। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 83 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। मंगलवार को बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी लिस्टिंग बिना किसी उतार चढ़ाव के 83 रुपये के स्तर पर ही हुई।

फ्लैट लिस्टिंग के बाद खरीदारों ने लिवाली शुरू कर दी, जिससे ये शेयर उछल कर 87 रुपये के स्तर तक पहुंच गया। बाजार में लगातार जारी खरीद बिक्री के बीच पहले एक घंटे का कारोबार होने के बाद सुबह 10:15 बजे ये शेयर 86.19 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे थे। इस तरह अभी तक के कारोबार के बाद कंपनी के आईपीओ निवेशक 3.84 प्रतिशत के फायदे में थे। याश्वी ज्वेलर्स का 43.88 करोड़ रुपये का आईपीओ 25 से 27 मई के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से एवरेज रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 5.64 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इनमें नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 3.40 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसी तरह रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 1.76 गुना सब्सक्राइब हो सका था।

इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 52,86,400 नए शेयर जारी किए गए हैं।

एलपीएल 2026 में होगा इम्पैक्ट सब नियम

हर टीम को खिलाना होगा अंडर-23 खिलाड़ी

एजेंसी (हि.स.)
कोलंबो

श्रीलंका प्रीमियर लीग (एलपीएल) 2026 में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आगामी सत्र में पहली बार इम्पैक्ट सब्स्टीट्यूट नियम लागू किया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक टीम के लिए प्लेइंग इलेवन में कम से कम एक अंडर-23 खिलाड़ी को शामिल करना अनिवार्य होगा। खास बात यह है कि इम्पैक्ट सब के इस्तेमाल के बाद भी टीम में अंडर-23 खिलाड़ी का होना जरूरी रहेगा।

सोमवार को कोलंबो में आयोजित एलपीएल 2026 ड्राफ्ट के दौरान इन नए नियमों की जानकारी दी गई। इन बदलावों के कारण सभी पांच फ्रेंचाइजी को अपनी टीमों का चयन काफी रणनीतिक तरीके से करना पड़ा। अंडर-23 खिलाड़ियों की सीमित उपलब्धता के कारण फ्रेंचाइजियों के सामने टीम संयोजन की चुनौती रही। कई प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी जुलाई में भारत के खिलाफ होने वाली अंडर-19 श्रृंखला के कारण टूर्नामेंट में उपलब्ध नहीं रहेंगे।

ड्राफ्ट के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि पथुम निसांका और मथीशा पथिराना चोट से जूझ रहे हैं। निसांका को वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम में शामिल किया गया है, लेकिन उनके कार्यभार को नियंत्रित किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार वह भारत के श्रीलंका दौरे से पहले पूरी तरह फिट होने के लिए सर्जरी भी करा सकते हैं।

चार टीमों के बदले नाम और नए मालिक

एलपीएल 2026 में चार फ्रेंचाइजियों ने नए मालिक और कोचिंग स्टाफ के साथ नए नाम भी अपनाए हैं। जो निम्न हैं... जाफना - एससी जाफना किंग्स, गॉल - गॉल ग्लैडिएटर्स, कैंडी - कैंडी रॉयल्स, कोलंबो -कोलंबो कैप्स, केवल दांबुला सिक्सर्स का नाम और पहचान यथावत रही।

ड्राफ्ट में इन खिलाड़ियों पर रही नजर

ड्राफ्ट में भारतीय क्रिकेटर विजय शंकर, उभरते तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा, पाकिस्तान के विस्फोटक बल्लेबाज साहिबजादा फरहान, अनुभवी एंजेलो मैथ्यूज और दिनेश चांदीमल जैसे खिलाड़ियों पर विशेष ध्यान रहा। इसके अलावा अविष्का फर्नांडो और चरिथ असलंका पहले दौर के प्रमुख चयन रहे, जबकि विदेशी खिलाड़ियों में रहमानुल्लाह गुरबाज और मोहम्मद नवाज सबसे चर्चित नाम रहे।

प्रमुख प्री-साइनिंग खिलाड़ी

एससी जाफना किंग्स: तस्किन अहमद, दुनिथ वेल्लालागे, शाकिब अल हसन, भानुका राजपक्षे। **गॉल ग्लैडिएटर्स:** लिटन दास, ईशान मलिंगा, रासी वान डेर डुसेन, दासुन शनाका। **कैंडी रॉयल्स:** विजय शंकर, एंजेलो मैथ्यूज, मोईन अली, वानिंदु हसरंगा। **कोलंबो कैप्स:** बेन मैकडरमॉट, कमिंदु मेंडिस, जिमी नीशम, कुसल मेंडिस। **दांबुला सिक्सर्स:** रीजा हेंड्रिक्स, दिनेश चांदीमल, साहिबजादा फरहान, दुष्मंथा चमीरा। एलपीएल 2026 में नए नियमों और बदले हुए टीम ढांचे के साथ टूर्नामेंट के और अधिक प्रतिस्पर्धी होने की उम्मीद की जा रही है। इम्पैक्ट सब और अंडर-23 नियम से युवा खिलाड़ियों को बड़ा मंच मिलने के साथ-साथ टीमों की रणनीति में भी नया आयाम देखने को मिलेगा।

महिला नेशंस कप के लिए भारतीय हॉकी टीम घोषित, सलीमा टेटे को मिली कप्तानी

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

हॉकी इंडिया ने मंगलवार को 15 से 21 जून तक न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित होने वाले एफआईएच महिला हॉकी नेशंस कप 2025-26 के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान एक बार फिर सलीमा टेटे को सौंपी गई है। भारत को प्रतियोगिता के पूल-ए में जापान, अमेरिका और उरुग्वे के साथ रखा गया है। टीम इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया दौरे से मिली सकारात्मक सीख और आत्मविश्वास के साथ उतरेगी। हाल ही में पर्थ में खेले गए चार मैत्री मैचों की श्रृंखला में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-2 की बराबरी हासिल की थी। गोलकीपिंग की जिम्मेदारी अनुभवी सविता और बिचू देवी खारीबाम संभालेंगी। रक्षा पंक्ति में सुशीला चानू पुखरामबाम, ईशिका चौधरी, निक्की प्रधान और ज्योति जैसी अनुभवी खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। वहीं लालथांतलुआंगी और शिल्पी डाबस भी टीम का हिस्सा हैं,

महिला हॉकी टीम

गोलकीपर: सविता, बिचू देवी खारीबाम। **डिफेंडर:** सुशीला चानू पुखरामबाम, ईशिका चौधरी, लालथांतलुआंगी, शिल्पी डाबस, ज्योति, निक्की प्रधान। **मिडफील्डर:** सलीमा टेटे (कप्तान), नेहा, सुनेलिता टोप्पो, साक्षी राणा, दीपिका सोरेंग, सोनम, लालरेमसियामी। **फॉरवर्ड:** नवनीत कौर, दीपिका, रुतुजा दादासो पिसाल, ईशिका, अन्नू।

जिन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सीनियर टीम में पदार्पण किया था। मध्यपंक्ति की अगुवाई कप्तान सलीमा टेटे करेंगी। उनके साथ नेहा, सुनेलिता टोप्पो, साक्षी राणा और दीपिका सोरेंग जैसी खिलाड़ी टीम को मजबूती देंगी।

ग्लोबल मार्केट से कमजोरी के संकेत, एशिया में मिला-जुला कारोबार

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

ग्लोबल मार्केट से मंगलवार को कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान बढ़त के साथ बंद होने में सफल रहे थे। हालांकि डाउ जॉन्स फ्यूचर्स मंगलवार को गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में पिछले सत्र के दौरान लगातार बिकवाली का दबाव बना रहा। वहीं एशियाई बाजार में मंगलवार को मिला-जुला कारोबार हो रहा है।

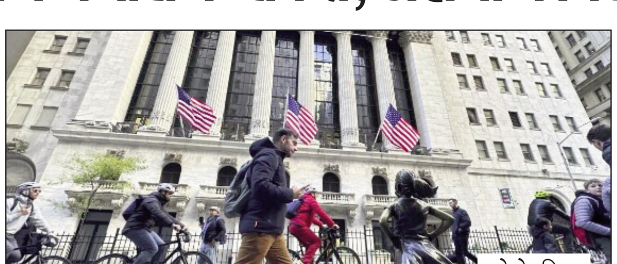
फोटो: हि.स.

अमेरिकी स्टॉक मार्केट में पिछले सत्र के दौरान टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में आई तेजी के कारण मजबूती का माहौल बना रहा। डाउ जॉन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.09 प्रतिशत की तेजी के साथ 51,078.88 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह एस एंड पी 500 इंडेक्स ने 0.26 प्रतिशत की मजबूती के साथ 7,599.96 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा नैस्डेक 114.19 अंक यानी 0.42 प्रतिशत की बढ़त के साथ 27,086.81 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं डाउ जॉन्स फ्यूचर्स मंगलवार को फिलहाल 201.85 अंक यानी 0.40 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 50,877.03 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है।

यूरोपीय बाजार में पिछले सत्र के दौरान लगातार बिकवाली होती रही। एफटीएसई इंडेक्स 0.68 प्रतिशत टूट कर 10,338.95 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह सीएसी इंडेक्स ने 0.45 प्रतिशत लुढक कर 8,146.59 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा डीएएक्स इंडेक्स 101.66 अंक यानी 0.41 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,003.04 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

एशियाई बाजार में मंगलवार को मिला-जुला कारोबार हो रहा है। एशिया के नौ बाजार में से पांच के सूचकांक गिरावट के साथ लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, जबकि चार सूचकांक मजबूती के साथ हरे निशान में बने हुए हैं। हैंग सेंग इंडेक्स मंगलवार को फिलहाल 348.82 अंक यानी 1.37 प्रतिशत की तेजी के साथ 25,747 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह सेट कंपोजिट इंडेक्स 0.94 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,583.04 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। इसके अलावा जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स 0.71 प्रतिशत उछल कर 6,171.01 अंक के स्तर पर और स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.44 प्रतिशत की छलांग लगा कर 5,059.82 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

दूसरी ओर, गिफ्ट निफ्टी 115.50 अंक यानी 0.49 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 23,326 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह ताइवान वेटेड इंडेक्स 286.52 अंक यानी 0.63 प्रतिशत टूट कर 45,051.39 अंक के स्तर पर आ गया है। कोस्पी इंडेक्स में मंगलवार को जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल यह सूचकांक 204.81 अंक यानी 2.33 प्रतिशत लुढ़क कर 8,583.57 अंक के स्तर पर पहुंच गया है। इसी तरह निक्केई इंडेक्स 1,069.33 अंक यानी 1.60 प्रतिशत फिसल कर 65,865 अंक के स्तर पर तक गिर गया है। इसके अलावा शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.04 प्रतिशत की मामूली कमजोरी के साथ 4,056.24 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है।

शुरूआती कारोबार में शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी की स्थिति में सुधार का रुख

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

घरेलू शेयर बाजार मंगलवार को शुरूआती कारोबार के दौरान निचले स्तर से रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है। कारोबार की शुरूआत कमजोरी के साथ हुई। बाजार खुलने के कुछ देर बाद ही खरीदारों ने लिवाली शुरू कर दी, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांक की चाल में सुधार होने लगा। हालांकि बीच-बीच में बिकवाली का झटका भी लगता रहा। इसके बावजूद ये दोनों सूचकांक लाल निशान में होने के बावजूद लगातार धीरे-धीरे रिकवर करते रहे। सुबह 10 बजे तक का कारोबार होने के बाद सेंसेक्स 0.23 प्रतिशत और निफ्टी 0.28 प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार करते नजर आए। 10 बजे तक का कारोबार होने के बाद स्टॉक मार्केट के दिग्गज शेयरों में से टेक महिंद्रा, इंफोसिस, कोल इंडिया, टीसीएस और जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर 3.99 प्रतिशत से लेकर 1.67

प्रतिशत की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। दूसरी ओर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, श्रीराम फाइनेंस, मैक्स हेल्थकेयर और आईटीसी के शेयर 3.21 प्रतिशत से लेकर 2.53 प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे थे। अभी तक के कारोबार में स्टॉक मार्केट में 2,734 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हो रही थी। इनमें से 1,258 शेयर मुनाफा कमा कर हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, जबकि 1,476 शेयर नुकसान उठा कर लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। इसी तरह सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में से छह शेयर लिवाली के सपोर्ट से हरे निशान में बने हुए थे। दूसरी ओर 24 शेयर बिकवाली के दबाव में लाल निशान में कारोबार कर रहे थे।

संक्षिप्त-समाचार

फ्रेंच ओपन: सबालेंका क्वार्टर फाइनल में ओसाका का सफर समाप्त

पेरिस। विश्व नंबर एक आर्यना सबालेंका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सोमवार को चार बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन नाओमी ओसाका को हराकर फ्रेंच ओपन 2026 के महिला एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। कोर्ट फिलिप शात्रिये पर खेले गए मुकाबले में बेलारूस की सबालेंका ने ओसाका को 7-5, 6-3 से मात दी। तीन वर्षों बाद आयोजित महिला नाइट-सेशन मुकाबले में सबालेंका ने शुरूआत से ही दबदबा बनाए रखा और सीधे सेटों में जीत दर्ज की। अब क्वार्टर फाइनल में उनका सामना रूस की डायना श्नाइडर से होगा। श्नाइडर ने पूर्व ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता मैडिसन कीज को 6-3, 3-6, 6-0 से हराकर अंतिम आठ में प्रवेश किया। फ्रेंच ओपन के पुरुष और महिला एकल ड्रॉ में अब सबालेंका ही एकमात्र सक्रिय ग्रैंड स्लैम चैंपियन बची हैं। वह रोलां गैरो की लाल मिट्टी पर अपना पहला खिताब जीतने की कोशिश कर रही हैं। पिछले वर्ष उन्हें फाइनल में कोको गॉफ से हार का सामना करना पड़ा था। यह लगातार 14वां ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, जिसमें सबालेंका क्वार्टर फाइनल तक पहुंची हैं। मैच के बाद सबालेंका ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी सर्विस इतनी अच्छी रहेगी। मुझे लगता है कि हर मैच के साथ मेरा खेल बेहतर हो रहा है और आज के प्रदर्शन से मैं बेहद खुश हूं। दूसरी ओर, सुनहरे परिधान में उतरी ओसाका का फ्रेंच ओपन में अब तक का सर्वश्रेष्ठ अभियान अंतिम-16 में समाप्त हो गया। एक अन्य मुकाबले में ऑस्ट्रिया की अनास्तासिया पोटापोवा को अन्ना कालिंस्काया के खिलाफ 6-4, 2-6, 7-6 (10-7) से हार का सामना करना पड़ा। कालिंस्काया अब पोलैंड की क्वालीफायर माया ख्वालिंस्का से भिड़ेंगी। माया ने फ्रांस की अंतिम बची खिलाड़ी डियान पैरी को 6-3, 6-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इस बीच, पेरिस के दर्शकों को भी जश्न मनाने का मौका मिला जब पेरिस सेंट-जर्मेन के खिलाड़ी उस्मान डेम्बेले, देजिरे डुए, वॉरेन जाइरे-एमरी और ब्रैडली बारकोला ने कोर्ट पर अपने लगातार दूसरे चैंपियंस लीग खिताब की ट्रॉफियों का प्रदर्शन किया।

वैभव सूर्यवंशी में दिखती है युवा सचिन की झलक : अतुल वासन

नई दिल्ली। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज अतुल वासन का मानना है कि युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के शुरूआती दौर की झलक दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि कम उम्र में सूर्यवंशी जिस परिपक्वता, आत्मविश्वास और साहस का प्रदर्शन कर रहे हैं, वह उन्हें 1989 के पाकिस्तान दौरे पर 16 वर्षीय सचिन तेंदुलकर की याद दिलाता है। हाल ही में समाप्त हुए आईपीएल सत्र में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने 16 पारियों में 237.30 के शानदार स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए और टूर्नामेंट के सबसे सफल बल्लेबाजों में शामिल रहे। सूर्यवंशी ने जसप्रीत बुमराह, कैगिसो रबाडा और पैट कमिंस जैसे विश्वस्तरीय गेंदबाजों के खिलाफ भी आक्रामक और निडर बल्लेबाजी की। वासन ने कहा कि सूर्यवंशी असाधारण प्रतिभा के धनी हैं और उनकी उम्र को देखते हुए उनका खेल बेहद परिपक्व नजर आता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह युवा सचिन ने पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाजों के सामने बिना किसी डर के बल्लेबाजी की थी, उसी तरह का आत्मविश्वास सूर्यवंशी में भी दिखाई देता है। पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा कि ईश्वर ने सूर्यवंशी को विशेष प्रतिभा, कौशल और शक्ति का वरदान दिया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस युवा खिलाड़ी को अभी लंबा सफर तय करना है और उम्मीद है कि उनका विकास भी तेंदुलकर की तरह सही दिशा में होगा।

हरिकांता ओवरसीज की स्टॉक मार्केट में निराशाजनक शुरूआत

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

सिंथेटिक टेक्सटाइल फैब्रिक का उत्पादन करने वाली कंपनी हरिकांता ओवरसीज के शेयरों ने मंगलवार को स्टॉक मार्केट में गिरावट के साथ एंट्री कर अपने आईपीओ निवेशकों को जबरदस्त झटका दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 91 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। मंगलवार को बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी लिस्टिंग 12.36 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ 79.75 रुपये के स्तर पर हुई। कमजोर लिस्टिंग के बाद बिकवाली शुरू हो जाने के कारण थोड़ी देर में ही कंपनी के शेयर गिर कर 75.77 रुपये के लोअर सर्किट लेवल तक आ गए। इस तर पहले दिन के कारोबार में ही कंपनी आईपीओ निवेशकों को प्रति शेयर 15.23 रुपये यानी 16.74 प्रतिशत का नुकसान हो गया। हरिकांता ओवरसीज का 24.30 करोड़ रुपये का आईपीओ 20 से 27 मई के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए

फोटो: हि.स.

खुला। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से फीका रिस्पॉन्स मिला, जिसके कारण ये ओवरऑल 1.12 गुना सब्सक्राइब हो सका। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 21.33 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में सिर्फ 0.70 गुना सब्सक्रिप्शन आया। इसी तरह रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन भी सिर्फ 66 प्रतिशत ही सब्सक्राइब हो सका। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 26.70 लाख नए शेयर जारी किए गए हैं।

महिला त्रिकोणीय टी२० सीरीज | प्रेंडरगास्ट रहीं मैच की नायिका

आयरलैंड ने पहली बार वेस्टइंडीज को हराया

एजेंसी (हि.स.)
डबलिन

आयरलैंड महिला टीम ने त्रिकोणीय टी20 श्रृंखला में इतिहास रचते हुए सोमवार देर रात वेस्टइंडीज को डकवर्थ-लुईस-स्टर्न (डीएलएस) पद्धति से 1 रन से हराकर टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ आयरलैंड ने फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को भी मजबूत कर लिया। मैच की नायिका कप्तान ओरला प्रेंडरगास्ट रहीं, जिन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन किया।

फोटो: हि.स.

पहले उन्होंने दो विकेट झटके और फिर नाबाद 71 रन की मैच विजयी पारी खेली। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की शुरूआत बेहद खराब रही। एवा कैनिंग ने पावरप्ले में दो विकेट लेकर कैरेबियाई टीम को शुरूआती झटके दिए। पांच ओवर के भीतर शीर्ष क्रम के बल्लेबाज पवेलियन लौट गए और टीम दबाव में आ गई। स्थिति तब और खराब हो गई जब स्टेफानी टेलर रन आउट होने के बाद चोटिल होकर रिटायर्ड हर्ट हो गईं। 10 ओवर के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर केवल 53/4 था और टीम को बड़े स्कोर के लिए मजबूत साझेदारी की जरूरत थी।

इसके बाद जैनिलिया ग्लासगो और शेमेन कैंपबेल ने पारी संभाली। दोनों ने महत्वपूर्ण साझेदारी कर टीम को संकट से निकाला। कैंपबेल के आउट होने के बाद प्रेंडरगास्ट ने डेथ ओवरों में दो विकेट लेकर वेस्टइंडीज की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। निचले क्रम के बल्लेबाजों के कुछ उपयोगी चौकों की बदौलत वेस्टइंडीज 20 ओवर में 141/8 तक पहुंचने में सफल रहा। 142 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आयरलैंड की शुरूआत भी खराब रही। शॉनिशा हेक्टर ने पारी की पहली चार गेंदों में ही दोनों सलामी बल्लेबाजों को आउट कर दिया। इसके बाद कप्तान प्रेंडरगास्ट ने मोर्चा संभाला। अपने 24वें जन्मदिन पर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए चौकों की झड़ी लगा दी। हालांकि वेस्टइंडीज ने बीच में लगातार तीन विकेट लेकर आयरलैंड को 65/5 के स्कोर पर मुश्किल में डाल दिया। लेकिन प्रेंडरगास्ट एक छोर पर डटी रहीं और तेजी से रन बनाती रहीं। 14 ओवर के बाद आयरलैंड का स्कोर 95/5 था, जिसमें अकेले प्रेंडरगास्ट के 71 रन शामिल थे। उस समय डीएलएस गणना के अनुसार आयरलैंड जीत से सिर्फ तीन रन पीछे था। इसी दौरान बारिश शुरू हो गई।

अंपायरों ने एक और गेंद फेंकने का फैसला किया और उस गेंद पर लुईस लिटिल ने किनारा लेकर चौका बटोर लिया। इसके बाद बारिश तेज हो गई और खिलाड़ियों को मैदान छोड़ना पड़ा।

संक्षिप्त स्कोर

वेस्टइंडीज महिला: 141/8 (20 ओवर), जैनिलिया ग्लासगो 36, शेमेन कैंपबेल 31, ओरला प्रेंडरगास्ट 2/26, एवा कैनिंग 2/11, आयरलैंड महिला: 99/5 (14.1 ओवर), ओरला प्रेंडरगास्ट 71, शॉनिशा हेक्टर 2/21, परिणाम: आयरलैंड महिला टीम 1 रन से विजयी (डीएलएस पद्धति)।

कटारिया ने जीएमसीएच सेक्टर-48 में विस्तारित स्वास्थ्य सेवाओं एवं नई ओपीडी का किया निरीक्षण

प्रशासक ने चंडीगढ़ में शिक्षा अधोसंरचना एवं पर्यावरणीय पहलों की भी समीक्षा की

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब के राज्यपाल एवं यू.टी. चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने आज शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने तथा नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा संचालित शैक्षणिक अधोसंरचना एवं पर्यावरणीय पहलों की भी समीक्षा की। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जीएमसीएच), दक्षिण परिसर, सेक्टर-48 में प्रशासक ने नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य सचिव श्री मंदीप सिंह बराड़ ने उन्हें आयुष ओपीडी, होम्योपैथी सेवाओं तथा आगामी पंचकर्मा सुविधा के बारे में जानकारी दी।

सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के महत्व पर बल देते हुए राज्यपाल ने लोगों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के प्रशासन के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार तथा चिकित्सा अधोसंरचना के उन्नयन के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि सभी नागरिकों को बेहतर उपचार एवं मरीजों की देखभाल सुनिश्चित की जा सके। प्रशासक ने फिजियोथेरेपी, इम्यूनाइजेशन, डे-केयर, ऑन्कोलॉजी, योग, डेंटल एवं बाल रोग ओपीडी सहित रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सेवाओं का भी निरीक्षण किया।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सेक्टर-47 एवं सिविल अस्पताल, सेक्टर-45 में प्रशासक के साथ स्वास्थ्य सचिव एवं निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. सुमन सिंह भी उपस्थित रहीं। प्रशासक ने मरीजों एवं उनके परिजनों से बातचीत कर उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के संबंध में फीडबैक लिया, जिस पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।

इसके उपरांत गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मलोया में प्रशासक ने मलोया समाधान शिविर के दौरान उठाए गए विद्यालय संबंधी मुद्दों की समीक्षा की। उन्हें अवगत कराया गया कि गवर्नमेंट हाई स्कूल, मलोया में अधोसंरचना को और मजबूत करने हेतु 25 कमरों के निर्माण के लिए टेंडर स्वीकृत कर दिया गया है। इस अवसर पर शिक्षा सचिव सुश्री प्रेरणा पुरी एवं निदेशक स्कूल शिक्षा श्री नितिश सिंगला भी उपस्थित रहे। इससे पूर्व दादू माजरा डंपिंग ग्राउंड स्थल पर प्रशासक ने जुलाई माह में प्रस्तावित वृक्षारोपण अभियान हेतु चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नगर निगम आयुक्त श्री अमित कुमार को निर्देश दिए कि मानसून के दौरान वृक्षारोपण गतिविधियों के सुचारु संचालन के लिए भूमि समतलीकरण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण किया जाए।

एनीमिया मुक्त हरियाणा अभियान को सफल बनाने के लिए सभी वर्गों की सहभागिता जरूरी : निशा यादव

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती निशा यादव की अध्यक्षता में आज लघु सचिवालय के सभागार में एनीमिया मुक्त हरियाणा अभियान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में एनीमिया (खून की कमी) को जड़ से समाप्त करने के लिए चलाए जा रहे प्रयासों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि एनीमिया मुक्त हरियाणा अभियान तभी सफल होगा जब समाज के सभी वर्ग मिलकर इस दिशा में योगदान दें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान की निगरानी नियमित रूप से की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र व्यक्ति आयरन की दवाओं से वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि एनीमिया को रोकने के लिए आयरन की प्रचुर मात्रा वाले खाद्य पदार्थ जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां (पालक, मेंथी, सरसों, बथुआ) अनाज(बाजरा) दाल और फलियां(चना, लोबिया, सोयाबीन) बादाम आदि तिलहन (मूंगफली) और गुड़ आदि सेवन करने चाहिए। भोजन से आयरन का अवशोषण बढ़ाने के लिए विटामिन सी की अधिकता वाले खाद्य पदार्थ जैसे ताजा हरी धनिया चटनी, दाल में नींबू का रस, अंकुरित दाले, सब्जी के सलाद, आँवला, नींबू, तरबूज, अमरुद, संतरा आदि का सेवन करें।

डॉक्टर शीनम, जिला नोडल अधिकारी ने बताया कि एनीमिया विशेषकर महिलाओं, गर्भवती माताओं और बच्चों में तेजी से फैलने वाली एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। इसे रोकने के लिए आयरन एवं फोलिक एसिड की नियमित खुराक, संतुलित आहार, और समय पर स्वास्थ्य जांच अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में एनीमिया जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि हर व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति का पता चल सके और उन्हें उचित उपचार उपलब्ध कराया जा सके। इसके अतिरिक्त नागरिकों में जनजागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाता है। निजी विद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे एनीमिया उन्मूलन माह के अंतर्गत शिविरों के आयोजन हेतु सक्रिय सहयोग प्रदान करें। साथ ही, विद्यालय स्तर पर हीमोग्लोबिन (एचबी) जांच तथा आयरन-फोलिक एसिड (आईएफए) अनुपूरण की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि सभी पात्र विद्यार्थियों को समय पर लाभ प्रदान किया जा सके। इस अवसर पर डिप्टी सिविल सर्जन आरबीएसके, एनएचएम, डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर, एनीमिया मुक्त हरियाणा पंचकूला, शिक्षा विभाग के सदस्य, प्रतिनिधि ब्लॉक एजुकेशन अफसर पिंजोर, प्रतिनिधि ब्लॉक एजुकेशन अफसर बरवाला, सभी अर्बन और रूरल डिस्पेन्सरिओ के अधिकारी, और आंगनवाड़ी अफसर मौजूद रहे।

उपायुक्त चंडीगढ़ ने निजी स्कूलों को छात्र सुरक्षा, रळफअढर नीति एवं पार्किंग मानकों के सख्त अनुपालन के निर्देश दिए

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

उपायुक्त चंडीगढ़ श्री निशांत कुमार यादव ने आज शहर के निजी स्कूल प्रबंधन के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में छात्र सुरक्षा, स्कूल परिवहन प्रबंधन, पार्किंग स्थलों के उपयोग, स्वीकृत भवन योजनाओं के अनुपालन तथा सेफ ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी फॉर स्टूडेंट्स नीति के क्रियान्वयन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान सभी निजी स्कूलों को निर्देश दिए गए कि छात्रों के चढ़ने और उतरने की प्रक्रिया स्कूल परिसर के भीतर ही सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित तरीके से सुनिश्चित की जाए। साथ ही किसी भी अप्रिय घटना से बचाव हेतु प्रशिक्षित स्टाफ की समुचित निगरानी भी सुनिश्चित करने को कहा गया। उन्होंने कई स्कूलों में निर्धारित पार्किंग स्थलों के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त की। यह पाया गया कि स्वीकृत भवन योजनाओं में चिन्हित पार्किंग स्थलों का उपयोग लॉन, खेल मैदान, स्विमिंग पूल, गार्ड रूम तथा शेड आदि अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। स्कूल प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि स्वीकृत पार्किंग स्थलों का उपयोग केवल स्कूल बसों एवं वाहनों की पार्किंग के लिए ही किया जाए तथा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उनका उपयोग न किया जाए। स्वीकृत भवन योजनाओं के अनुपालन को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए गए। उपायुक्त ने आगाह किया कि किसी भी प्रकार का अनधिकृत निर्माण, स्वीकृत नक्शे से विचलन अथवा निर्धारित लेआउट का दुरुपयोग गंभीर उल्लंघन माना जाएगा तथा संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त सभी निजी स्कूलों को बिना किसी विलंब के रळफअढर नीति को पूर्ण रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए। यह नीति विद्यार्थियों के सुरक्षित परिवहन हेतु व्यापक दिशा-निर्देश प्रदान करती है तथा इसका अनुपालन सभी स्कूलों के लिए अनिवार्य किया गया है।

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि छात्र सुरक्षा, पार्किंग मानकों अथवा भवन योजना अनुपालन से संबंधित किसी भी प्रकार के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के नए प्रावधानों के प्रति लोगों को करें जागरूक : अतिरिक्त उपायुक्त

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती निशा यादव ने आज लघु सचिवालय के सभागार में जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति की आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने निर्देश दिए कि जिलावासियों को जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के नए प्रावधानों से जागरूक किया जाए। जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम के तहत शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला, ड्राइविंग लाईसेंस और वोटर लिस्ट बनाने, विवाह पंजीकरण, पासपोर्ट और आधार कार्ड बनाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है। इसके अलावा मृत्यु के ऐसे मामले जिनमे पुलिस कार्यवाही जारी है, संबंधित पुलिस स्टेशन के आईओ को नजदीकी रजिस्ट्रेशन सैंटर को मृत्यु की जानकारी देना अनिवार्य है। जिला में कुल 15 जन्म और मृत्यु पंजीकरण केंद्र संचालित हैं। अतिरिक्त उपायुक्त ने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ अन्य संबंधित विभागों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए कि वे जन्म और मृत्यु पंजीकरण अवश्य करवाएं ताकि वे विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में नोटिस बोर्ड के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए कि स्कूल में दाखिला लेने के लिए जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक है। नोडल अधिकारी जन्म-मृत्यु डाक्टर संदीप जैन ने बताया कि जिला में जन्म और मृत्यु पंजीकरण का कार्य बेहतरीन ढंग से किया जा रहा है। सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत इस सेवा को तय समय सीमा में लोगों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जनवरी 2026 से मई 2026 तक जन्म और मृत्यु पंजीकरण से संबंधित कुल 4526 मामलों को पूरा किया जा चुका है। बैठक में एसडीएम कालका संयम गर्ग, पंचकूला तहसीलदार सुरेश कुमार, महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ सविता नेहरा, जिला शिक्षा अधिकारी संध्या मलिक, डीसीओ प्रवीण कुमार, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ आजाद सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

मांग में अचानक और तेजी से वृद्धि के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) पंजाब में निर्बाध ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित कर रही

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) - इंडियनऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल - देश भर में परिचालन और लॉजिस्टिक्स समन्वय जारी रखे हुए हैं ताकि कई क्षेत्रों में ईंधन की मांग में अचानक और तीव्र वृद्धि के बावजूद पेट्रोल (एमएस), डीजल (एचएसडी) और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। हाल के दिनों में, ओएमसी ने कई राज्यों में मौसमी कृषि गतिविधियों और कटाई कार्यों के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की उल्लेखनीय रूप से अधिक खपत देखी है। अन्य आपूर्तिकताओं की तुलना में कम कीमत के कारण खुदरा ग्राहकों के सार्वजनिक क्षेत्र के खुदरा आउटलेट्स की ओर रुख करने और संस्थागत और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के खुदरा ईंधन आउटलेट्स की ओर स्पष्ट रुझान के कारण भी अतिरिक्त मांग का दबाव उत्पन्न हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसी अपने टर्मिनलों, डिपो, पाइपलाइनों, एलपीजी बॉटलिंग संयंत्रों और खुदरा आउटलेट्स के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के माध्यम से निर्बाध आपूर्ति बनाए हुए हैं। आपूर्ति दल, परिवहन नेटवर्क, टर्मिनल संचालन और चुनिंदा खुदरा आउटलेट्स बाजारों में निर्बाध उत्पाद आवागमन और समय पर पुनःपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 2477 कार्यरत हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां निर्बाध ईंधन आपूर्ति के लिए राज्य प्रशासन के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाए हुए हैं। तेल उद्योग उपभोक्ताओं को आश्वस्त करना चाहता है कि देशभर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां स्टॉक की स्थिति की लगातार समीक्षा कर रही हैं और बढ़ी हुई मांग को कुशलतापूर्वक पूरा करने के लिए रसद और वितरण योजना पर घनिष्ठ समन्वय स्थापित कर रही हैं। आईओसीएल पंजाब राज्य कार्यालय के कार्यकारी निदेशक व राज्य प्रमुख श्री अशुतोष गुप्ता, जो पंजाब में तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयक भी हैं, ने कहा कि नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे सामान्य खरीदारी जारी रखें और अनावश्यक रूप से घबराकर खरीदारी करने से बचें। उपभोक्ताओं से यह भी अनुरोध है कि वे ईंधन की उपलब्धता से संबंधित सटीक जानकारी के लिए केवल अधिकृत एजेंसियों और तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।

आईटीआई पंचकूला में नशे के विरुद्ध एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कण्ट्रोल ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री संजय कुमार के दिशानिर्देशों एवं पुलिस उप-महानिरीक्षक श्री राजेंद्र कुमार मीणा के मार्गदर्शन में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सेक्टर 14 पंचकूला में नशे के विरुद्ध एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजकीय आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य मनदीप बेनीवाल की उपस्थिति में यह कार्यक्रम हुआ जिसमें 150 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। उच्चाधिकारियों के आदेश से ब्यूरो के जागरूकता कार्यक्रम एवं पुनर्वास प्रभारी/ उप निरीक्षक डॉ. अशोक कुमार वर्मा संस्थान में पहुंचे और एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों बारे विस्तार से समझाकर नशा मुक्त समाज के निर्माण में सहभागिता करने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि नशा भावी पीढ़ियों के लिए अभिशाप है। उन्होंने बताया कि नशा मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। नशा मनुष्य के जीवन में शौक बनकर आता है और उसके जीवन का अंत शोक में परिवर्तित हो जाता है। उन्होंने बताया कि यदि नशा अच्छा होता तो सबसे पहले माँ अपने बच्चे को नशा करने के लिए देती।

कार्यक्रम के अंत में शपथ ग्रहण करवाई गई। इस अवसर पर वर्ग अनुदेशक अनुदेशक एवं छात्र छात्राएं आदि उपस्थित रहे।

संक्षिप्त-समाचार

जीएमएसएच-16 के ब्लड बैंक में लगी मामूली आग पर काबू पाया गया

चंडीगढ़। जीएमएसएच-16 के ब्लड बैंक में 02 जून 2026 की दिन निकलने से पहले प्रातःकाल एक मामूली आग की घटना हुई। तत्परता एवं प्रभावी कार्रवाई के चलते स्थिति को शीघ्र ही नियंत्रित कर लिया गया, जिससे किसी बड़े नुकसान अथवा सेवाओं में बाधा उत्पन्न नहीं हुई। यह घटना सबसे पहले ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों द्वारा देखी गई, जिन्होंने तुरंत सुरक्षा कर्मियों को सूचित किया। सुरक्षा कर्मियों ने बिना विलंब प्रतिक्रिया देते हुए आग पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया, जिससे आग के फैलने को रोका जा सका। अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारियों, जिनमें निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ , मेडिकल सुपरिंटेंडेंट , डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट तथा ब्लड बैंक प्रभारी शामिल हैं, ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा ब्लड बैंक की आवश्यक सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश तुरंत जारी किए गए। प्रारंभिक आकलन के अनुसार, आग लगने का संभावित कारण ब्लड बैंक क्षेत्र में स्थापित एयर-कंडीशनिंग यूनिट में शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम हेतु विस्तृत तकनीकी जांच जारी है।

जुलाई 2026 सत्र के लिए इग्नू में नए प्रवेश शुरू

पंचकूला। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने जुलाई 2026 के शैक्षणिक सत्र के लिए अपने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) और ऑनलाइन कार्यक्रमों में नए प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। योग्य आवेदक अब विश्वविद्यालय द्वारा पेश किए जाने वाले स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों की विस्तृत श्रृंखला के लिए आवेदन कर सकते हैं। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र चंडीगढ़ के वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉ भानु प्रताप सिंह ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 15 जुलाई 2026 तक खुली रहेगी। इच्छुक उम्मीदवार इग्नू के आधिकारिक प्रवेश पोर्टल लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डॉ भानु प्रताप सिंह ने आवेदकों को सलाह दी है कि वे आवेदन जमा करने से पहले इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कार्यक्रम विवरण, पात्रता शर्तें, शुल्क संरचना और प्रवेश दिशानिर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

21 जून को मनाया जाएगा 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

पंचकूला। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, स्वास्थ्य, आयुष मंत्री सुश्री आरती सिंह राव एवं श्री संजीव वर्मा महानिदेशक आयुष विभाग हरियाणा के निदेर्शानुसार 21 जून 2026 को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2026 मनाया जा रहा है। जिला प्रशासन पंचकूला के सहयोग से डा0 दिलीप कुमार मिश्रा जिला आयुर्वेदिक अधिकारी की अध्यक्षता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2026 के अवसर पर जिला पंचकूला के खण्ड स्तर पर योग आसन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ताउ देवी लाल स्टेडियम, सैक्टर-3 आज पंचकूला में, राजीव गाँधी खेल स्टेडियम, बरवाला एवं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नानकपुर में आयुष विभाग, खेल विभाग एवं शिक्षा विभाग पंचकूला द्वारा योग आसन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 163 प्रतिभागियों ने भाग लिया। हरियाणा सरकार की फिट हरियाणा पहल को इन कार्यक्रमों से नई गति मिल रही है। योग के माध्यम से स्वस्थ शरीर और सशक्त मन के निर्माण की दिशा में यह एक सशक्त जन-अभियान बनता जा रहा है। योग आसन प्रतियोगिता का उद्देश्य योग को जन-जन तक पहुचाना है ताकि सभी स्वस्थ जीवन जी सकें।

कालका एट बिटना राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 2026-27 सत्र के इच्छुक छात्रों के लिए दाखिला पोर्टल शुरू

पंचकूला/कालका । कालका एट बिटना स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के इच्छुक छात्रों के लिए दाखिला पोर्टल शुरू कर दिया है। इंजीनियरिंग व गैर इंजीनियरिंग ट्रेड्स में दाखिले के लिए 15 जून तक आवेदन किया जा सकता है। प्रधानाचार्य श्री मनदीप बेनीवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि दाखिले से संबंधित दिशा-निर्देश, संस्थानों की सूची तथा सीट मैट्रिक्स की पूरी जानकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। उन्होंने बताया कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी, जिसके तहत अभ्यर्थियों को अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी हागी। उन्होने बताया कि दाखिले के लिए शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, ई-मेल आईडी तथा सक्रिय मोबाइल नंबर अनिवार्य होंगे। अन्य बोर्ड से आने वाले विद्यार्थियों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी जमा करवाना होगा। दाखिले के लिए आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लिए जाएंगे, जिसके लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 100 रुपए और आरक्षित वर्ग के लिए 50 रुपए रहेगा। महिला आवेदको के लिए दाखिला आवेदन निशुल्क रहेगा। उन्होने बताया कि विभाग के अनुसार यदि किसी विद्यार्थी की पढ़ाई में गैप रहा है, तो उसे गैप ईयर का शपथ पत्र तथा बैंक पासबुक की कॉपी भी आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के निदेर्शानुसार दो वर्षीय आईटीआई करने के बाद कक्षा बारहवीं का हिंदी या अंग्रेजी विषय का पेपर देने पर छात्र बारहवीं की मार्कशीट प्राप्त कर सकते है।

पंचकूला में तंबाकू विरोधी अभियान, कई दुकानों पर जुर्माना

पंचकूला। हरियाणा के खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त श्री मनोज कुमार और अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती निशा यादव के निदेर्शों पर कार्रवाई करते हुए चार सदस्यों की एक टीम ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा), 2003 के उल्लंघनों पर नकेल कसने के लिए पंचकूला की विभिन्न दुकानों में अचानक निरीक्षण किया। प्रवर्तन टीम, जिसमें एनटीसीपी के नोडल अधिकारी डॉ. संदीप जैन, खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. आजाद सिंह और औषधि नियंत्रक अधिकारी प्रवीण कुमार शामिल थे, ने प्रमोद पान (सेक्टर 14), अजय पान (सेक्टर 5), मनोज ढाबा (सेक्टर 22), अमित पटेल (सेक्टर 15) और पिंटू पान भंडार (सेक्टर 5) का निरीक्षण किया। अधिनियम का पालन न करने के लिए इनमें से प्रत्येक प्रतिष्ठान पर 200 रुपये का जुमार्ना लगाया गया। इसके अलावा, सेक्टर 5 में पंडित पान पर छापेमारी के दौरान, टीम ने विवेक पटेल को रोका और एस्से लाईट सिगरेट के 27 पैकेट, साथ ही मोंड ब्लूबेरी-फ्लेवर वाली सिगरेट के 6 पैकेट जब्त किए। इनमें से किसी भी पैकेट पर अनिवार्य सचित्र स्वास्थ्य चेतावनी नहीं थी। इस उल्लंघन का कड़ा संज्ञान लेते हुए, टीम ने कोटपा 2003 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज कराने के लिए सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है।

आदेश — अतिरिक्त उपायुक्त ने राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता की

शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बिक्री पर सख्त निगरानी के निर्देश

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती निशा यादव ने कहा कि शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में बीड़ी, सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। यदि कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा), 2003 के तहत चालान सहित आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और उन्हें किसी भी बुरी लत से बचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। समाज, अभिभावकों और शिक्षकों के संयुक्त प्रयासों से ही बच्चों को नशे जैसी बुराइयों से दूर रखा जा सकता है।

अतिरिक्त उपायुक्त आज लघु सचिवालय के सभागार में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के संबंध में गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति की आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। श्रीमती निशा यादव ने निर्देश दिए कि स्कूलों में विशेष रूप से 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों पर निगरानी रखी जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे किसी प्रकार की नशे की लत का शिकार न हों। उन्होंने कहा कि दोपहर के भोजन अवकाश तथा स्कूल की छुट्टी के समय विद्यालयों और उनके आसपास 100 मीटर की परिधि में रैंडम चेकिंग की जाए। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कोई भी विक्रेता खाद्य पदार्थों की आड़ में नशीले पदार्थों की बिक्री न कर रहा हो। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों को स्वस्थ, सुरक्षित और नशामुक्त वातावरण प्रदान करना है।

श्रीमती निशा यादव ने कहा कि सिगरेट एवं तंबाकू उत्पादों का सेवन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। इसके सेवन से शरीर में अनेक गंभीर और जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा), 2003 के तहत होटल, रेलवे स्टेशन, सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यालय, बस स्टैंड, सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि सिगरेट, बीड़ी या किसी अन्य माध्यम से धूम्रपान करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 200 रुपये तक का जुमार्ना लगाया जा सकता है।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण एवं छापेमारी अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के चालान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा बैनर, पोस्टर और पंपलेट के माध्यम से लोगों को धूम्रपान एवं तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाए। इसके अलावा सभी सार्वजनिक कार्यालयों, संस्थानों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर ह्लयहां धूम्रपान करना निषेध हैह्व संदेश वाले पोस्टर प्रमुखता से लगाए जाएं, ताकि लोगों में तंबाकू नियंत्रण कानूनों के प्रति जागरूकता बढ़े और उनका प्रभावी पालन सुनिश्चित हो सके।

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डॉ. संदीप जैन ने बताया कि धूम्रपान तथा तंबाकू, गुटखा और खैनी जैसे उत्पादों का सेवन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। इनके सेवन से दमा, सांस संबंधी समस्याएं, लगातार खांसी, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, पक्षाघात (अधरंग), मधुमेह, आंखों में जलन और मोतियाबिंद जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। बैठक में एसडीएम कालका संयम गर्ग, पंचकूला तहसीलदार सुरेश कुमार, महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ सविता नेहरा, जिला शिक्षा अधिकारी संध्या मलिक, डीसीओ प्रवीण कुमार, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ आजाद सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।